RNI No.DELHIN/2011/41355

दिल्ली से प्रकाशित

अक्टूबर 2025 वर्ष 14 अंक 167 मूल्य₹20

प्राइम स्पेक्टेटर

राजनीति पीएसयू और अपराध पर केंद्रित पत्रिका

PRIME INDIA MEDIA HOUSE →

PRIME CRIME INDIA
www.primecrimeindia.com

PSU TODAY

NETA INDIA
www.netaindia.com

LONDON DAIRY
Premium Ice Cream
SHEER INDULGENCE
LONDON DAIRY
Premium Ice Cream
DOUBLE CHOCOLATE
LONDON DAIRY
Premium Ice Cream
NEW FIG WALNUT
LONDON DAIRY
Ice Cream with Yoghurt
mango
londondairy.in
londondairyindia
londondairy.com

संपादकीय

नासिर खान
संपादक

लेह में हिंसा समाधान नहीं

पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख में चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अगुआई में लंबे वक्त से यह मांग है और इसे लेकर केंद्र से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन, इस दौरान हिंसा का हो जाना चिंताजनक है।

सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35। के प्रावधान हटाने के साथ ही जम्मू–कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया था। तब सरकार ने वादा किया था कि हालात सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि 6 साल बाद लोगों का भरोसा और सब्र डगमगाने लगा है। लेह में हुए प्रदर्शन को ळमद–ʃ का आंदोलन कहा जा रहा है। कुछ दिनों पहले यही पीढ़ी नेपाल में सत्ता बदल चुकी है। लेकिन, नेपाल और लद्दाख की तुलना नहीं की जा सकती। और न ही हिंसा को किसी भी तरह जायज ठहराया जा सकता है। सोनम वांगचुक का पूरा आंदोलन अहिंसक रहा है। सरकार से मतभेद होने के बावजूद उन्होंने बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा। उनके समर्थन में खड़े युवाओं को भी इसी व्यवहार का पालन करना चाहिए। हिंसा से समस्या और जटिल हो जाएगी।

समाधान के लिए लद्दाख के लोगों की चिंता पर संवेदनशीलता से विचार करने की जरूरत है। उनमें यह डर है कि अगर शासन उनके हाथ में न रहा तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होगा। छठी अनुसूची स्वायत्त और स्वशासन के कुछ विशेष अधिकार देती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र इस सूची के तहत सुरक्षित हैं।

बीएमसी चुनाव से पहले विजयादशमी पर मुंबई में राजनीतिक पार्टियों ने किया शक्ति प्रदर्शन

प्राइम स्पेक्टेटर

संपूर्ण हिंदी मासिक पत्रिका

DAVP No.0813F27125-025

वर्ष-14, अंक:167, अक्टूबर 2025

मूल्य ₹ 20

RNI No.DELHIIN/2011/41355

संपादक
नासिर खान

सलाहकार संपादक
डॉ. ईशा
राकेश त्रिपाठी

राजनीतिक सपादक
इंजी.ए पी सिंह

संपादक (सूचना प्रौद्योगिकी)
प्रशांत दत्त मिश्रा

कानूनी सलाहकार
डी.बी.गोस्वामी,सलीम खान
(एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)

चीफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव
समीर अख्तर

विदेश प्रतिनिधि
विकास पारिक (लंदन)

प्रमुख प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो प्रमुख
सतपाल सिंह तंवर

लखनऊ ब्यूरो प्रमुख
अशोक तिवारी

मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख
श्वेतांक वर्मा

हरियाणा ब्यूरो प्रमुख
संजय सिन्हा

उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख
सुनील नेगी

पूर्वांचल ब्यूरो प्रमुख
शाहिद अस्करी

सोनभद्र ब्यूरो प्रमुख
संजय सिंह

बरेली मण्डल ब्यूरो प्रमुख
योगेंद्रपाल सिंह कौशल

बिहार ब्यूरो प्रमुख
शक्ति प्रकाश

महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख
राजकुमार केशरवानी

हिमाचल ब्यूरो प्रमुख
साहिल शर्मा

राजस्थान ब्यूरो प्रमुख
रानू पाठक

पश्चिम बंगाल,दिल्ली एनसीआर ब्यूरो प्रभारी
नरेश कुमार श्रीवास्तव

बिहार: 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान-7

बरेली में बवाल: पथराव-फायरिंग-30

संपादकीय 3

भारत, विश्व में सर्वप्रथम हो : शाह 16

पीएसयू की खबरें 32

तमिलनाडु- रैली में भगदड़ 38

'ब्रेन ईटिंग अमीबा' बीमारी से मौत 40

रफूगरी का है जमाना 48

बौल्या काका नवंबर में होगी रिलीज 49

क्षेत्रीय प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो
मोहम्मद आसिफ (वरिष्ठ संवाददाता)
मथुरा ब्यूरो
विनय चौधरी (संवाददाता)
कानपुर ब्यूरो
अजय कुमार द्विवेदी (वरिष्ठ संवाददाता)
इलाहाबाद ब्यूरो
गुफरान खान (वरिष्ठ संवाददाता)
मीरजापुर ब्यूरो
संजीव कुमार जैन (वरिष्ठ संवाददाता)
बलिया ब्यूरो
डॉ.कलीम वारसी (वरिष्ठ संवाददाता),
आरा ब्यूरो
विमलेश कुमार (संवाददाता)
हाजीपुर ब्यूरो
राहुल कुमार (संवाददाता)

कार्यालय

कॉरपोरेट ऑफिस
91, फर्स्ट फ्लोर जे एंड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली– 110092
संपादकीय कार्यालय
आर–141/3 रमेश पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली–110092
मोबाइल–9718647540Ph.011-46536014
ईमेल–primespectator@gmail.com,primeindia-mediahouse@gmail.com
वेबसाइट–primeindiamediahouse.com
primecrimeindia.com & netaindia.com

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक नासिर खान द्वारा ANEJA PRINTERS,C–11,SECTOR-10,NOIDA (UP) से मुद्रित तथा आर–141/3 रमेश पार्क,लक्ष्मी नगर,दिल्ली–110092 से प्रकाशित। सभी पदाधिकारी अवैतनिक हैं। प्राइम स्पेक्टेटर के किसी भी रचना के प्रकाशन से पहले संपादक की अनुमति अनिवार्य है। पत्रिका में प्रकाशित लेख,लेखक के निजी विचार हैं। सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

बिहार
विधानसभा चुनाव
2025 कब?

बिहार: 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान, 14 नवंबर को घोषित होंगे नतीजे

डॉ. ईशा
सलाहकार संपादक

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आगामी छह नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा तथा मतगणना 14 नवंबर होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीट के लिए मतदान होगा। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीट हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि चुनाव के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर को होगी, 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को होगी, 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उनके अनुसार, राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जिनमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ और महिला मतदाता 3.50 करोड़ हैं। कुमार ने बताया कि 14 लाख मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान कर सकेंगे। बिहार की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया था, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में राज्य के बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं। राज्य में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड–19 महामारी की पृष्ठभूमि में तीन चरणों में हुए थे।कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि किसी का नाम छूट गया है, तो नामांकन की तिथि से 10 दिन पहले तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कुमार ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल कानून व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि पूर्ण पारदर्शी तरीके से होने वाले ये चुनाव सबसे अच्छे चुनाव परिलक्षित हों, ऐसी आयोग की मंशा है। उन्होंने कहा कि आयोग सभी राजनीतिक दलों और सभी लोगों से सहयोग की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाए। कुमार ने कहा कि फर्जी खबरों और दुष्प्रचार पर आयोग की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 17 नई पहल की जा रही हैं, जो बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगी। इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा।

जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना व राजस्थान में उपचुनाव 11 नवंबर को

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान की आठ विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे तथा मतगणना 14 नवंबर को होगी। कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव 11 नवंबर को होंगेय मतगणना 14 नवंबर को होगी। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट रामदास सोरेन के निधन के कारण रिक्त हो गयी थी। पंजाब की तरनतारन विधानसभा सीट कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हो गई।

जम्मू कश्मीर में दो विधानसभा क्षेत्र - बडगाम और नगरोटा – अक्टूबर 2024 से रिक्त हैं। बडगाम सीट 2024 के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद रिक्त हो गई थी, जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने

गांदरबल सीट को अपने पास रखने का फैसला किया था। यह सीट 21 अक्टू.बर, 2024 से रिक्त है। नगरोटा सीट विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद 31 अक्टूबर, 2024 को रिक्त हुई थी। राजस्थान के अंता में उपचुनाव धमकी दिए जाने के एक मामले में भाजपा विधायक कंवरलाल को दोषी ठहराए जाने के बाद मई में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद आवश्यक हो गया। तेलंगाना का जुबली हिल निर्वाचन क्षेत्र इस साल जून में बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ का निधन होने से रिक्त हो गया था। मिजोरम की डम्पा विधानसभा सीट 21 जुलाई को एमएनएफ के निवर्तमान विधायक लालरिंतलुआंगा सैलो के निधन के बाद रिक्त हो गई थी। ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट आठ सितंबर को निवर्तमान विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन के कारण रिक्त हो गयी थी।

मतदान केंद्रों के फुटेज केवल उच्च न्यायालयों के साथ साझा किए जा सकते हैं: ज्ञानेश

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज केवल उच्च न्यायालयों के साथ साझा किए जा सकते हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जनता के साथ साझा करना मतदाताओं की निजता का उल्लंघन है। कुमार का कहना था कि मतदान की वेबकास्टिंग फुटेज फॉर्म 17ए के समान है, जिसे उन मतदाताओं की पहचान की सुरक्षा के लिए राजनीतिक दलों के साथ साझा नहीं किया जाता है जिन्होंने मतदान किया। बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कुमार ने कहा कि ऐसे फुटेज संबंधित उच्च न्यायालय के साथ साझा किए जाते हैं जहां किसी विशेष चुनाव के परिणाम के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की जाती है। चुनाव संचालन नियमों के अनुसार, फॉर्म 17ए, जिसमें मतदान केंद्र पर मतदान करने वाले मतदाताओं के नाम होते हैं, उन्हें अदालतों के अलावा किसी और के साथ साझा नहीं किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि बिहार के दियारा क्षेत्र में 250 मतदान केंद्रों पर गश्त के लिए पुलिस घोड़ों का इस्तेमाल करेगी, जबकि 197 मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मतदान दल नावों का इस्तेमाल करेंगे। कुमार ने बताया कदियारा क्षेत्र में कम से कम 250 मतदान केंद्रों पर पुलिस घोड़ों के जरिए गश्त करेगी। इसी तरह, 197 मतदान केंद्रों पर मतदान दल नाव से यात्रा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। कुमार ने मतदाताओं को बड़ी राहत की खबर देते हुए यह भी कहा कि आयोग आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने के लिए काउंटर स्थापित करेगा।

बुर्कानशीं मतदाताओं की पहचान के लिए मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे आंगनवाड़ी सेविकाएं

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 'बुर्कानशीं या पर्दानशीं मतदाताओं की पहचान के लिए मतदान केंद्रों पर आंगनवाड़ी कर्मी उपलब्ध रहेंगी तथा आवश्यकता होने पर तय निर्देशों के तहत पहचान का सत्यापन होगा। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने से संबंधित संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। कुमार से सवाल किया गया कि बुर्के या घूंघट में आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? इसके जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जहां तक बुर्कानशीं की बात हो रही है, पर्दानशीं की बात है, तो पहचान के लिए हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं उपलब्ध रहेंगी। जरूरत पड़ने पर जांच होगी। निर्वाचन आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि मतदान केंद्र के कैसे पर पहचान का सत्यापन होगा और उनका कड़ाई से पालन होगा। इससे पहले, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीते शनिवार को निर्वाचन आयोग से विधानसभा चुनाव एक या दो चरणों में कराने और मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर पहुंचने वाली महिलाओं के चेहरे का मिलान मतदाता पहचान पत्र से करने की मांग की थी।

बेरोजगारी, पलायन और विशेष राज्य का दर्जा बन सकते हैं प्रमुख चुनावी मुद्दे

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य का चुनावी माहौल गर्माने लगा है। बढ़ती बेरोजगारी, विशेष राज्य के दर्जे की मांग, जातीय आरक्षण और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे मुद्दे इस बार चुनाव प्रचार के दौरान छाए रह सकते हैं। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन अगले महीने होने वाले इस चुनाव में आमने–सामने होंगे। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राज्य में दो चरणों

ें में मतदान की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजग का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हें अब भी राज्य की राजनीति में एक दमदार चेहरा माना जाता है। गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अलावा जीतन राम मांझी, चिराग पा. सवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी दल शामिल हैं। वहीं, विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल (राजद)–कांग्रेस कर रहे हैं, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)–माले–लिब. रेशन सहित कई अन्य सहयोगी दल शा. मिल हैं। गठबंधन 2020 के विधानसभा चुनाव में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित है और इस बार सत्ता में वापसी के लिए आक्रामक रुख अपनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनाव मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर लड़ा जाएगा, जिनमें मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआ. ईआर) एक प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के नेता लगातार निर्वाचन आयोग पर "वोट चोरी" का आ. रोप लगाते रहे हैं हालांकि आयोग ने इन आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में अप. राध दर बढ़ी है और प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर हुआ है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन का दावा है कि राज्य में कानून–व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस तंत्र प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। राज्य सरकारों द्वारा हाल ही में शुरू की गई कई जनकल्याण योजनाएं राजग के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गयी योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। वहीं विपक्ष इस बात पर जोर देगा कि नीतीश कुमार सरकार ने कई वादों को पूरा नहीं किया है।राज्य से लगातार हो रहा श्रमिकों और युवाओं का पलायन इस बार भी बड़ा मुद्दा रहेगा।विपक्षी दल राजग सरकार पर राज्य में पर्याप्त रोजगार अवसर न सृजित करने और युवाओं को बाहर जाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाते रहे हैं लेकिन अब विपक्ष

इसी मुद्दे पर राजग को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा के साथ जदयू की लंबे समय की साझेदा. री के बावजूद यह मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। राज्य में हाल में हुई जातीय गणना और उसके बाद वंचित वर्गों के आरक्षण में वृद्धि का श्रेय दोनों गठबंधन अपने–अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग के बाद यह मुद्दा "मंडल बनाम कमंडल" की राजनीति को फिर से जीवित कर सकता है, जहां एक ओर सामाजिक न्याय की राजनीति होगी, वहीं दूसरी ओर हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर मतदाता ध्रुवीकरण की संभावना। विश्लेषकों का कहना है कि इस बार का बिहार चुनाव विकास व शासन बनाम सामाजिक न्याय व अवसर की राजनीति के बीच दिलचस्प मुकाबला हो सकता है।

नीतीश के नेतृत्व में राजग सत्ता में वापसी की राह पर : एसडब्ल्यूओटी

चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को बि. हार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी 'इंडियाश गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया है। जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग जहां एक और कार्यकाल की उम्मीद कर रहा है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से मिलकर बने इंडिया गठबंधन का लक्ष्य सत्ता से राजग को बेदखल करना है। यहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग के लिए एक एसडब्ल्यूओटी (ताकत, कम. जोरियां, अवसर, खतरे) विश्लेषण किया गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार राजग के सबसे मजबूत स्तंभ हैं और उनके नेतृत्व में गठबंधन को कई स्तरों पर बढ़त हासिल है। राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने लगभग दो दशकों के शासन में प्रशासनिक स्थिरता और कल्याणकारी योजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। इनमें घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, ग्रामीण इलाकों में पेयजल की आपूर्ति और अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार सृजन का वादा प्रमुख हैं। राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि नीतीश कुमार की "सुशासन" की छवि, भाजपा और जदयू का संगठित कैडर नेटवर्क और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य में शुरू की गई आधारभूत ढांचा परियोजनाएं राजग की प्रमुख ताकत हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं भी मतदाताओं के बीच लोकप्रिय मानी जा रही हैं। हालांकि, लगभग दो दशकों (2005–2010) से सत्ता में रहने के कारण नीतीश कुमार के शुरुआती कार्यकाल

की ताजगी अब कम हो गई है। सत्ता विरोधी लहर इस बार एक प्रमुख चुनौती बन सकती है।इसके अलावा, भाजपा के सामाजिक आधार को लेकर यह धारणा बनी हुई है कि वह अभी भी अग. ड़ी जातियों की पार्टी है, जिनकी आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का केवल करीब 10 प्रतिशत है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक चरम काल के बाद जदयू में द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व का अभाव भाजपा के लिए संगठनात्मक विस्तार और नेतृत्व में जगह बनाने का अवसर पैदा करता है। साथ ही, प्रधानमंत्री मा. ेदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ भी राजग को मिल सकता है। भाजपा के भीतर अन्य दलों से आए नेताओं को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, जिसे पार्टी के लिए प्रदूषणकारी प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। वहीं हाई कमांड संस्कृति, जो पहले कांग्रेस से जोड़ी जाती थी, अब भाजपा में भी महसूस की जा रही है। इसके अलावा, हिंदुत्व विचारधारा पर अत्यधिक निर्भरता मुस्लिम मतदाताओं, विशेष रूप से पासमांदा समुदाय को दूर कर सकती है जिन्हें नीतीश कुमार के सामाजिक संतुलन की राजनीति ने अब तक जोड़े रखा था। राजनीतिक विश्लेष. कों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जहां विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता को मुद्दा बना रहा है, वहीं राजग विकास और स्थिर शासन की अपनी थीम पर जनता से समर्थन मांगने की रणनीति पर काम कर रहा है।

विधानसभा चुनाव में सभी सीट पर बसपा अपने बलबूते लड़ेगी : मायावती

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में होने वाले मतदान की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस चुनाव में सभी सीट पर अपने बलबूते लड़ेगी। बसपा प्रमुख ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि बहुप्रतीक्षित बिहार राज्य विधानसभा चुनाव के लिये दो चरणों में छह और 11 नवम्बर को मतदान कराने की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गयी घोषणा का स्वागत। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग व्यापक जन व देशहित तथा देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान की व्यवस्था जनता की चाह के मुताबिक करेगा। मायावती ने उम्मीद जताई कि आयोग वास्तविक रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा धन व बाहुबल के अभिशाप से मुक्त कराने के साथ ही पु. लिस व सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से पा. क–साफ होना सुनिश्चित करने के लिये सख्त व प्रभावी कदम उठायेगा। उन्होंने अपने भतीजे का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द के नेतृत्व में 'सर्वजन हिताय जागरण यात्राश आदि का भी सफल आयोजन किया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि बिहार के लोग अपने राज्य में कानून द्वारा कानून का राजश की आदर्श व्यवस्था के लिए 'सर्वजन हिताय व सर्व. जन सुखाय' के पक्ष में 'हाथीश चुनाव चिह्न पर मतदान कर बसपा उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनायेंगे।

हर बिहारी बनेगा मुख्यमंत्री, बिहार चुनाव बदलाव का पर्व : तेजस्वी यादव

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव बदलाव का पर्व होगा और हर बिहारी मुख्यमंत्री बनेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानस. भा चुनाव की तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने 'एक्सश पर एक भावनात्मक पोस्ट के माध्यम से मतदाताओं से अपील की। उन्होंने लिखा, "बिहार आने वाले विधानसभा चुन. ावों में बदलाव के लिए मतदान करेगा। 20 साल बाद एक भव्य पर्व आएगा जो दुख और तकलीफों को मिटा देगा। उस दिन हर बिहारी तेजस्वी के साथ जीत का जश्न मनाएगा क्योंकि उस दिन हर बिहारी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा यानी चेंज मेकर।" मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने की घोषणा की। तेजस्वी ने पोस्ट में कहा कि मेरे प्यारे बि. हारवासियों, 14 नवंबर 2025 ,यह तारीख याद रखिए। यह दिन बिहार के उज्जवल भविष्य, परिवर्तन, विकास और उत्थान की स्वर्णिम शुरुआत के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। बदलाव का बिगुल बज चुका है। अब हर बिहारी को पूरे समर्पण और ऊर्जा के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए आगे आना है। पूर्व सरकार में उपमुख्यमंत्री रह चुके यादव ने दावा किया कि बिहार के युवा बेरोजगारी खत्म करने के लिए वोट देंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सबको सरकारी नौकरी देगा। जो राजग सरकार 17 साल में नहीं कर सकी, हमने 17 महीने में कर दिखाया। जो काम इस सरकार ने 20 साल में नहीं किया, हम उसे 20 महीने में पूरा करेंगे। तेजस्वी ने कहा, "सबके सहयोग से हम एक बेहतर, विकसित और नया बिहार बनाएंगे। यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर प्रहार किया और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, घोटालों और खराब सार्वजनिक ढांचे जैसी समस्याओं को गिनाया, जिनसे बिहार

पिछले दो दशकों से जूझता रहा है। उन्होंने लिखा कि 20 साल से बिहार ने दर्द, पीड़ा, अपराध, हिंसा, हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, भयावह अपराध जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, रिश्वत, भ्रष्टाचार, 100 से अधिक घोटाले, शोषण, पेपर लीक, जनादेश की चोरी, लाठीचार्ज, महिलाओं का अपमान, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़... सब कुछ झेला है। यादव ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हुए कहा कि बिहार को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो दूरदर्शी, निडर और गरीबों, दलितों तथा वंचितों के अधिकारों के प्रति समर्पित हो। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसा नेता चाहिए जो साहसी, ऊर्जावान, दूरदर्शी, निर्भीक, स्वाभिमानी, सिद्धांतवादी, संस्कारी और समाजवादी हो जो गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ सके। तेजस्वी ने अंत में मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और भरोसा जताया कि बिहार इस बार बदलाव के पक्ष में मतदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं बल्कि बिहार में बदलाव के पर्व की शुरुआत है। दिवाली और छठ पूजा के बाद बिहार के 20 साल का इंतजार खत्म होगा।

बिहार में राजग फिर बनाएगी सरकार, प्रचंड बहुमत मिलेगा : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बिहार इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सोमवार को विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) राज्य में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद दिलीप जायसवाल ने 'एक्सश पर कहा कि राजग का हर कार्यकर्ता राज्य के विकास और समृद्धि के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता विकास को चुनेगी और बिहार को विकसित व आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के लिए एक बार फिर राजग को बहुमत देगी। आइए हम सब एकजुट होकर बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। राजग दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा।" उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी 'एक्सश पर कहा, "जनता एक बार फिर राजग सरकार को चुनेगी। यह समय है अपने अधिकारों का समझदारी से उपयोग करने का और अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने का... राज्य में राजग सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को पहचानिए।" उन्होंने कहा, "बुनियादी ढांचे, सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में राजग सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के लिए एक बार फिर राजग को वोट दें। आइए, विकसित बिहार के सपने को साकार करें।"

भाजपा-जदयू सरकार के अंत की शुरुआत, बिहार बदलाव को तैयार: कांग्रेस

कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष राजेश राम ने सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)–जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के 'कुशासन' का अंत शुरू हो गया है और अब राज्य बदलाव के लिए तैयार है। राजेश राम ने निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद कहा कि पिछले 20 वर्ष से बिहार ने अंधकार, भय और भ्रष्टाचार का बोझ झेला है। अब जनता जवाबदेही की शुरुआत करेगी और भ्रष्टाचार तथा घोटालों का अंत करेगी, जिन्होंने बिहार की रीढ़ तोड़ दी। उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2024 की रिपोर्ट ने उजागर किया कि 70,877 करोड़ की राशि का कोई हिसाब नहीं है और 49,649 योजनाएं बिना उपयोग प्रमाणपत्र के पड़ी रहीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्ष में 3.59 लाख करोड़ का बजट खर्च ही नहीं किया जबकि बच्चों की शिक्षा, अनुसूचित जाति–जनजाति कल्याण, कृषि और शहरी विकास जैसे क्षेत्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। राजेश ने आरोप लगाया कि भाजपा–जदयू की सरकार ने बिहार को लूट का 'एटीएमश बना दिया, जहां गरीबों के हक का पैसा अफसरों और माफियाओं के खातों में गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अपराध और अराजकता ने 'सुशासन' के दावे की पोल खोल दी है।उन्होंने कहा,एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में प्रतिदिन औसतन 16 हत्याएं और 20 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं दर्ज होती हैं। 2025 के पहले छह महीनों में ही 1,376 हत्याएं हुईं।" राजेश राम ने कहा कि यह डबल इंजन नहीं, 'ट्रबल इंजनश सरकार है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को भाजपा–जदयू सरकार की "सबसे बड़ी विफलता" बताया। राजेश राम के अनुसार, "बिहार में चिकित्सकों की 60 प्रतिशत कमी, अस्पतालों में 93 प्रतिशत बेड की कमी और दवाइयों की 50 प्रतिशत कमी है।" कांग्रेस नेता ने गरीबी और पलायन के मुद्दे पर कहा कि बिहार की 64 प्रतिशत आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही है और 94 लाख परिवार 200 रुपए प्रतिदिन या उससे कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "तीन करोड़ पंजीकृत मजदूरों में से 94 प्रतिशत की मासिक आय 10,000

रुपये से कम है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही बिहार में जवाबदेही की सुबह शुरू हो गई है। भाजपा–जदयू ने 20 वर्ष तक बिहार की जनता को अपराध, गरीबी और पलायन का दंश दिया। अब जनता ने मन बना लिया है भाजपा–ज. दयू के भ्रष्टाचार का अंत होगा और महागठबंधन के साथ बिहार आगे बढ़ेगा।" उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि "नीति परिवत. न, व्यवस्था परिवर्तन और विश्वास की वापसी" का चुनाव होगा।

बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होने की तारीख तय हो गई : प्रशांत

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही 'राज्य के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होने की तारीख तय हो गई है'। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार के लोग किसी दल या नेता के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करेंगे। किशोर ने निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा किये जाने के बाद पत्रकारों से कहा, "पिछली बार दोनों गठबंधनों को मिलाकर 72 प्रतिशत मतदान हुआ था। शेष 28 प्रतिशत वोट इस बार जन सुराज को मिलेगा। अगर दोनों गठबंधनों को 10–10 प्रतिशत का नुकसान होता है, तो वे वोट जन सुराज में जुड़ जाएगा और हमारा वोट प्रतिशत 48 हो जाएग. ा।" उन्होंने कहा, "हमें 'वोटकटवा पार्टी' कहा गया है लेकिन हम इसे अपने लिए एक मेडल मानते हैं। हम दोनों गठबं. धनों का इतना वोट काटेंगे कि वे साफ हो जाएंगे। किशोर ने दो चरणों में चुनाव कराने के आयोग के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा निर्णय है। पहले अधिक चरणों में चुनाव इसलिए कराए जाते थे ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अधिक सभाएं कर सकें। लेकिन अब भाजपा भी समझ चुकी है कि मोदीजी की सभाओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसलिए जल्दी चुनाव निपटाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि आज बिहार के लोगों की बंधुआ मजदूरी खत्म होने की ता. रीख घोषित हुई है। अब बिहार के लोग मोदी–नीतीश या लालू के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करेंगे। हमारा सपना है कि बिहार ऐसा राज्य बने, जहां उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग भी पढ़ाई और रोजगार के लिए आएं। किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध. ते हुए कहा, "नीतीश कुमार ने हाल में पटना मेट्रो का उद्घाटन किया है। यह उनका अंतिम उद्घाटन था। हमने पहले ही कहा था कि अगली बार वे मुख्यमंत्री आवास 'अणे मार्ग' पर दही–चूड़ा नहीं खाएंगे। इससे पहले, जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने भी चुनाव की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि इस बार चुनाव दिवाली और छठ के बाद होंगे। त्योहार के दौरान बाहर से जो लोग अपने घर लौटेंगे, वे बिहार में बदलाव के लिए मतदान करेंगे।

विधानसभा की सभी 243 सीट पर लड़ेगी 'आप'

आम आदमी पार्टी (आप) ने बिहार में विधानसभा की सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए राज्य की राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश किया।'आप' के बिहार प्रभारी अजेश यादव ने पटना में संवाददाताओं से कहा कि पार्टी दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार और विकास के मॉडल को बिहार में दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, "हमारे पास शासन और विकास का प्रमाणित मॉडल है। आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दिल्ली की जीत में पूर्वांचल के लोगों का बड़ा योगदान रहा था।" यादव ने कहा, "हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब दिल्ली में सरकार बनाने में बिहार के लोग हमारी मदद कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं?" पहली सूची में जिन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं उनमें बेगूसराय से मीरा सिंह, पूर्णिया जिले की कसबा विधानसभा सीट से भानु भारतीय, पटना की फुलवारी सीट से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर सीट से पंकज कुमार, मोतिहारी की गोविंदगंज सीट से अशोक कुमार सिंह और बक्सर सीट से सेवा. निवृत्त कैप्टन धर्मराज सिंह शामिल हैं। राज्य के सह प्रभारी अभिनव राय ने स्पष्ट किया कि पार्टी किसी भी राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा, "हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। हम किसी दल या मोर्चे से समझौता नहीं करेंगे।"यादव ने दिल्ली व पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल पर कहा, "प्रशांत किशोर अब सुधारों की बात कर रहे हैं, जबकि हमने उन्हें पहले ही जमीन पर उतार दिया है।" यादव ने बताया कि पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की सूची शीघ्र जारी करेगी। उन्होंने कहा, "हमारे शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और भगवंत मान पहले भी बिहार का दौरा कर चुके हैं।"

राजग और 'इंडिया' गठबंधन की किस्मत का फैसला करेंगे 7.42 करोड़ मतदाता

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दो चरणों में मतदान की घोषणा के साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया। पहले चरण के लिए छह नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस बार 7.42 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वर्तमान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भा. जपा) के पास सबसे अधिक 80 विधायक हैं जबकि उसकी सहयोगी जदयू के पास 45 विधायक हैं। केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के चार विधायकों के समर्थन से राजग का कुल आंकड़ा 129 पर पहुंचता है

बीएमसी चुनाव से पहले विजयादशमी पर मुंबई में राजनीतिक पार्टियों ने किया शक्ति प्रदर्शन

शिवसेना के दोनों गुटों एकनाथ शिंदे-उद्धव ठाकरे ने की रैलियां, खूब सियासी बाण छोड़े गए

मुंबई। मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन (बीएमसी) के चुनाव नजदीक आते ही महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। विजयदशमी के दिन पूरे महाराष्ट्र में पांच रैलियां आयोजित हुईं। इनमें दोनों शिवसेना गुटों की रैलियों के अलावा आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर नागपुर में रैली हुई जिसे मोहन भागवत ने संबोधित किया। वहीं पंकजा मुंडे और मनोज जरांगे पाटील ने भी रैली निकाल. कर अपना दम दिखाया। मोहन भागवत ने अपनी रैली में सरकार और समाज में दूरी से जेन जेड में गुस्सा है। उनके इस बयान सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से जोड़ा गया, तो वहीं मुंबई में शिवसेना के दोनो खेमों के नेता एक-दूसरे पर बरसे। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के साथ बीजेपी को घेरा तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने अपनी हमले में उद्धव ठाकरे पर चुन-चुनकर हमले किए। इन तीन रैलियों के अलावा महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे और मनोज जरांगे पाटील ने भी अपना दम दिखाया।

रैलियों में एक दूसरे पर की जमकर बयानबाजी

गोरेगांव में दशहरा रैली पर एकना. थ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को साजिश प्रमुख बताया। शिंदे ने कहा कि बीएमसी चुनावों में उनकी (उद्धव ठाकरे) की परछाई भी नहीं बचेगी। शिंदे ने उद्धव ठाकरे के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर भी तंज कसा और कहा कि बाढ़ के कीचड़ में रैंप बिछाए गए थे। रैंप वॉक चल रहा था। एक बिस्कुट का पैकेज ले गए थे। शिंदे ने कहा कि आप सिफ लेना बैंक है। देना बैंक नहीं है। शिंदे ने कहा कि मैंने सिर्फ देने का काम किया है। मेरे हाथ खाली नहीं है। लाखों शिवसैनिकों के हाथ मेरे हैं। शिंदे ने आगे कहा कि बालासाहेब के विचार ही मेरी संपती हैं। शिंदे ने दावा किया कि बीएमसी में महायुति का भगवा लहराएगा।

मुंबई को बिकने नहीं देंगे

उद्धव ठाकरे अपने भाषण में शिंदे खिंचाई करते हुए कहा कि महायुति सरकार मुं. बई की जमीन उद्योगपति गौतम अडानी को देने का काम क रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा

कि वह नगर निकाय चुनावों में जीत के बाद बीजेपी की लूट के खिलाफ एक श्वेत पत्र लेकर आएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य को भाषा के आधार पर राजधानी मिली। हम मुंबई को नीलाम नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे के भाषण के दौरान बारिश भी हुई लेकिन शिवसेना यूबीटी प्रमुख बोलते रहे। शिवाजी पार्क में संजय राउत भी बोले। उन्होंने कहा कि 68 साल पहले शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की जगाई हुई चिंगारी की अलख हैं। जो आज धधकती मशाल बनकर पूरे राज्य में छा गई है।

रैली के बाद सोशल मीडिया पर नेताओं ने कसे तंज

मुंबई में शिवसेना की दशहर रैलियां खत्म होने के बाद अब सड़क की लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। दोनों अपनी रैली को हिट और दूसरे की रैली को फ्लॉप बता रहे हैं। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे की रैली पर तंज कस रहे। उन्होंने एक्स पर उद्धव की सभा के वीडियो को री–पोस्ट करके लिखा है कि जो पार्टी 288 में से 109 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 20 सीटें जीतने की क्षमता रखती है। उसकी सभा का वास्तविक दृश्य। ऊपर से शिवसेना प्रमुख यह सब देखकर कितने कुपित होते होंगे। इसका अंदाज बायलॉजिकल वारिसों को नहीं होगा, तो वहीं उद्धव गुट के नेता शिंदे की रैली को फ्लॉप करार दे रहे हैं। शिंदे ने पहली रैली आजाद मैदान में रखी बाद में उन्होंने बारिश को देखते हुए रैली नेस्को प्रदर्शनी स्थल पर शिफ्ट कर ली थी।

शिंदे और उद्धव के बीच हुई डायलॉगबाजी

शिवसेना की दशहरा रैलियों पर पूरे महाराष्ट्र की नजर रहती है। इस बार के मुकाबले को शिंदे बनाम उद्धव देखा गया था। महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने कहते हैं कि उद्धव ठाकरे चूंकि विपक्ष में हैं। ऐसे में वह किसी भी मुद्दे पर बोले सकते हैं लेकिन शिंदे के साथ ऐसा नहीं था। शिंदे सरकार में हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी स्पीच को काफी टू द प्वाइंट रखा, लेकिन उद्धव ठाकरे पर अटैक भी किया। नेने कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के संबोधन नयापन नहीं था। वे जिन मुद्दों पर पहले बोल चुके हैं। उन्होंने उन्हीं मुद्दों को उठाया। नेने कहते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे जमीन बचानी है तो जमीन के मुद्दे उठाने होंगे। नेने कहते हैं कि दोनों रैलियों में एक–दूसरे के ऊपर पर भी डायलॉगबाजी ही ज्यादा हुई। नेने कहते हैं उद्धव ने बारिश के बीच भीगते हुए भाषण देकर जरूर शिवसैनिकों को एक मैसेज देने की कोशिश की। मनोज जरांगे पाटिल ने दशहरा रैली में राज्य में गीला सूखा घोषित करने की मांग की, तो पंकजा मुंडे ने दशहरा रैली में सरकार से कहा कि मराठों को आरक्षण दें लेकिन ओबीसी का हक मारकर नहीं।

असली शिवसेना आज भी हमारे पास है : उद्धव ठाकरे

शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी दशहरा रैली में कहा कि असली शिवसेना आज भी उनके पास है। उन्होंने उन ने. ताओं की आलोचना की जो पार्टी छोड़कर चले गए और शिंदे गुट में शामिल हो गए। ठाकरे ने कहा कि जनता अब भी हमारे साथ है और पार्टी की असली पह. चान उन्हीं में है। यही लोग असली सोना हैं, बाकी जाने वाले लोग तो पीतल के हैं। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अब 'अमीबा' बन गई है, एक कोशिकीय जीव की तरह जो कहीं भी फैलती रहती है। यदि यह पेट में चला जाए, तो तकलीफ होती है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के विस्तार और सत्ता की लालसा को भी चुनौती दी।

भाजपा नेताओं पर पर साधा निशाना

साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और शासन में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। ठाकरे ने कहा कि अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। शराब के लाइस. ेस मंत्रियों के नाम पर जारी किए जा रहे हैं और डांस बार उनके परिवार की महिलाओं के नाम से खोले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक सर्वे का भी जिक्र किया और बताया कि कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री टॉप 5 में आते थे, लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस 10वें स्थान पर हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बने, जबकि ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, एम.के. स्टालिन, पिनाराई विजयन और अन्य नेता उनसे आगे हैं। ठाकरे ने कहा कि यह जनता की नाकामी नहीं, बल्कि मौजूदा नेतृत्व की असफलता है।

पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर उठाए सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया मणिपुर दौरे पर भी ठाकरे ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले तीन साल से जल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब जाकर दौरा किया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि मोदी ने वहां केवल इतना कहा कि "मणिपुर के नाम में ही मणि है", लेकिन उन्होंने राज्य की पीड़ा और वहां के लोगों के आंसू नहीं देखे। ठाकरे ने कहा कि यह लोगों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है।

हिंदू-मुस्लिम के बीच फूट डालने की कोशिश

पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा एक बार फिर हिंदू–मुस्लिम के बीच विभाजन की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सुशा. सन से कोई लेना–देना नहीं है। नागपुर में आरएसएस की विजयादशमी रैली को लेकर ठाकरे ने सवाल किया कि क्या आप आरएसएस की 100 साल की मेहनत से पैदा हुए जहरीले फलों से संतुष्ट हैं?

सोनम वांगचुक मामले में भी केंद्र पर साधा निशाना

उद्धव ठाकरे ने लेह के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को लेकर भी केंद्र सर. कार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब तक वांगचुक मोदी की तारीफ करते रहे, तब तक उन्हें राष्ट्रवादी बताया गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया, उन्हें निशाने पर ले लिया गया। ठाकरे ने सवाल किया कि अगर पाकिस्तान जाने पर किसी को देशद्रोही कहा जाता है तो फिर उन नेताओं का क्या जो वहां आधिकारिक दौरे पर जाते हैं।

हम दिल्ली जाते हैं विकास के लिए, वे जाते हैं 10 जनपथ पर मुजरा करने के लिए: शिंदे

गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाते हैं महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र की विकास योजनाओं को गति देने के लिए और वे (ठाकरे परिवार) 10 जनपथ में मुजरा करने जाते हैं। शिंदे ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर गुणगान की और बालासाहेब ठाकरे के सपनों को पूरा करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कोई भी माई का लाल मुंबई का महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता। मुंबई महाराष्ट्र की है, मराठी माणूस की है और मराठी माणुस की ही रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन मराठियों को मुंबई से बाहर किया उन्हें हम मुंबई लाकर रहेंगे। दशहरा रैली के लिए शिंदे का जगह बदलना फायदेमंद रहा। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर शिंदे उद्धव ठाकरे पर गरज रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने 20 मिनट से ज्यादा समय बाढ़ ग्रस्त किसानों की मदद करने पर बोला। उनकी सरकार और उनके शिवसैनिक किसानों की मदद कर रहे हैं। तो दूसरी ओर वे हमारी आलोचना कर रहे हैं कि मदद के ट्रक में शिंदे की फोटो लगी। शिंदे तो देता है। शिंदे लेना बैंक नहीं, देना बैंक है। उनके पास हमारी आलोचना के अलावा कोई काम नहीं है। उद्धव का नाम लिए बिना शिंदे ने कहा कि उन्हें चाहिए काजू बादाम, पानी में उतरे तो सर्दी जुकाम। शिंदे ने कहा कि लोकसभा जीती, विधानसभा जीती और अब स्थानीय निकाय चुनाव जीतकर महायुति का भगवा लहराना है। शिंदे ने जोर देकर कहा कि लाडली बहना योजना बंद रही होगी। इसका वे वचन देते हैं। शिंदे ने कहा कि यह स्थगित सरकार नहीं प्रगति सरकार है। हमने विकास के सभी स्पीड ब्रेकर हटा दिए। विकास योजना शुरू हुई। ढाई साल में बहुत काम किया। अब दूसरी पारी शुरू है। हम व देवेंद्र फडणवीस मिलकर काम कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र निवेश में पहले नंबर पर, स्टार्टअप में पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र विकास में नंबर वन है। महाराष्ट्र उद्योग फ्रेंडली राज्य है।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

प्रधानमंत्री ने तय किया, 2047 तक भारत हर क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम हो : शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम के जन्मदिन पर दिल्ली को लगभग 1723 करोड़ रुपए की सौगातें

दिल्ली सरकार पीएम के जन्मदिन पर 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया। इस दौरान दिल्ली में 75 सौगातें दी गईं

नरेश कुमार श्रीवास्तव
दिल्ली एनसीआर ब्यूरो प्रभारी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया। इसके तहत पीएम के जन्मदिन 17 अक्टूबर के दिन दिल्ली को 17 सौगातें दी गई। 17 सितंबर को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार की लगभग 1723 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि 15 अगस्त, 2047 को भारत हर क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम हो। अमित शाह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने संकल्प रखा था कि अब भारत को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का समय आ गया है। उन्होंने तय किया कि 15 अगस्त, 2047 को भारत हर क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम हो और पूरे देश की जनता को इस संकल्प के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि एक विकसित, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरूआत में अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली सरकार की लगभग 1723 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केन्द्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, महापौर और मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में बुधवार को नरेला–बवाना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की शुरुआत हुई है। इससे तीन हजार टन कचरे और ओखला प्लांट में दो हजार मीट्रिक टन कचरे से बिजली बनाने की व्यवस्था होगी जिससे सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ेगी और ग्रीन एनर्जी भी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को शर्मिंदा करने वाले बड़े–बड़े कूड़े के पहाड़ से मोदी सरकार बिजली बनाने की शुरुआत कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनता के उपयोग की हर वस्तु पर अब 28 और 18 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत और शून्य प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी के उपयोग की 395 चीजो पर या तो कर को शून्य या 5 प्रतिशत कर दिया है। शाह ने कहा कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को न सिर्फ सुविधाएं दी, बल्कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम भी किया है। शाह ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना और 60 करोड़ लोगों के जीवन में प्राथमिक सुविधाएं देना एक बहुत बड़ा प्रयत्न और संकल्प है। उन्होंने कहा कि आज की यह शुरुआत देश के हर युवा को प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से प्रेरणा लेकर सेवा के रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित करेगी। शाह ने कहा कि लोगों से अपील की कि वह स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदें। इससे हम मिलकर एक समृद्ध भारत का संकल्प सिद्ध कर सकेंगे।

घुसपैठियों के दम चुनाव जीतना चाहते हैं विपक्षी दल

केन्द्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में लोगों से पूछा कि क्या हमारी मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि वह घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालकर किसे बचाना चाहता है। शाह ने कहा कि घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालने वाले मुख्य विपक्षी दल के नेता घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी चाहती है कि घुसपैठिये हमारी मतदाता सूची में बने रहें क्योंकि विपक्षी पार्टी

को भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है और वह घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी एसआईआर और मतदाता सूची को शुद्ध करने के अभियान का समर्थन करती है।

दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकारें दिल्ली के साथ करती थीं भेदभाव

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजधानी दिल्ली में किसी भी पार्टी की सरकार हो प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भेदभाव नहीं किया और दिल्ली को जो भी मिलना चाहिए था हमेशा उससे ज्यादा ही दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें दिल्ली के साथ भेदभाव करती थीं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा लाई गई 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा की योजना को दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार ने लागू नहीं किया था। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है और अपना पूरा जीवन देश के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया है।

पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में राम मंदिर सहित कई लंबित मामलों को समाप्त किया

अमित शाह ने कहा कि पूरे देश की लंबे समय से इच्छा थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने और पीएम मोदी के कार्यक. ाल में वहां भव्य मंदिर बन गया है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, सोमनाथ मंदिर को फिर से सोने का बनाने की शुरुआत करनी हो या करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाना हो, सालों से लंबित ऐसे कई मसलों को पीएम मोदी ने समाप्त कर दिया। वहीं देश से धारा 370 को हटाने का काम पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कर दिखाया। शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने 24 साल के अपने सार्वजनिक सेवा के कार्यकाल में कभी छुट्टी नहीं ली है। पीएम मोदी 24 साल तक हर पल, हर क्षण, देश के विकास की चिंता और गरीबों के कल्याण में लगे रहे। उन्होंने कहा कि इसी कारण हम विश्व की 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और 2027 तक हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे।

विकसित दिल्ली की ओर तेजी से बढ़ रही है राजधानी : रेखा गुप्ता

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली की ओर अग्रसर हो रही है। यह बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित लोकार्पण समारोह में अपने अध्यक्षीय संबोधन में कही। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्र अमित शाह का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दृढ़ वाणी और संकल्प ने हमेशा भारत की सुरक्षा को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग को याद किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने सत्ता को कभी विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना, इसलिए वे हर जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष 17 सितम्बर को गृह मंत्री अमित शाह के हाथों 17 योजनाओं का उद्घ. ाटन हुआ और 15 दिनों में 75 योजनाएं दिल्लीवासियों को समर्पित की जाएंग. ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली पहली बार देख रही है कि बिना भेदभाव और बिना राजनीति के केंद्र सरकार से इतना व्यापक सहयोग मिल रहा है।मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लोकार्पित की गई पर. ियोजनाओं का विवरण देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा के क्षेत्र में कई नई पहलें शुरू की हैं, जो राजधानी को और अधिक विकसित, सु. रक्षित और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगी। स्व. च्छता और ऊर्जा के क्षेत्र में नरेला–बवाना में 3000 टन प्रतिदिन क्षमता वाला नया वेस्ट–टू–एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही ओखला प्लांट

का विस्तार कर उसकी क्षमता 1950 टन से बढ़ाकर 2950 टन प्रतिदिन कर दी गई है। यह कदम दिल्ली को सतत ऊर्जा और स्वच्छता की दिशा में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

पांच नए अस्पतालों में ब्लॉक्स और 101 आरोग्य मंदिर जनता को किए गए समर्पित

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार ने पांच नए अस्पताल ब्लॉक और 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 150 नई डायलिसिस मशीनें भी जनता को उपलब्ध कराई गई हैं।

दिव्यांग बच्चों के लिए 10 नए रिसोर्स सेंटर्स स्थापित

शिक्षा और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। दस नए रिसोर्स सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, जहां 12 हजार 500 बच्चों को स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और आधुनिक तकनीकों की मदद से सहयोग मिलेगा। यह प्रयास दिल्ली के बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहा है। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। पश्चिम विहार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावित्रीबाई फुले होम, तिमारपुर में दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए अटल दृष्टि होम और नरेला में 220 बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए आधुनिक पुनर्वास सुविधाओं से युक्त अटल आशा होम की स्थापना की गई है। हाई सपोर्ट नीड्स वाले दिव्यांगजनों को 6,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, वहीं वृद्धावस्था वित्तीय सहायता योजना में 50,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है।

75 एआई-सक्षम ड्रोन दिल्ली पुलिस को सौंपे गए

सुरक्षा और तकनीक को लेकर भी दिल्ली सरकार ने अग्रणी कदम उठाए हैं। नेत्रदृनारीदृनेतृत्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिल्ली के छात्रों द्वारा बनाए गए 75 एआई–सक्षम ड्रोन दिल्ली पुलिस को महिला पुलिस के प्रशिक्षण हेतु सौंपे गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली फायर सर्विस को 24 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल्स भी प्रदान किए गए हैं, ताकि तंग गलियों में भी आगजनी जैसी आपात स्थितियों का तुरंत सामना किया जा सके।

तीन नए शैक्षिक पाठ्यक्रमों का शुभारंभ

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़े के तहत तीन नए शैक्षणिक पाठ्यक्रमों नीव (नव उद्यम और उद्यमिता विकास योजना, जीवन का विज्ञान तथा राष्ट्रीय नीति का औपचारिक शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है, जो छात्रों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें जीवन कौशल, उद्यमिता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और जिम्मेदार नागरिकता के साथ सशक्त बनाएगा। भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, सम्बंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य मौजूद थे। इस पाठ्यक्रम को दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने विकसित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना है, जिसमें शैक्षणिक शिक्षा के साथ–साथ महत्वपूर्ण जीवन कौशल और नागरिक जिम्मेदारी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में लाखों विद्यार्थियों के लिए देश निर्माण के दृष्टिकोण से तीन नए करिकुलम लांच किए गए हैं। इन करिकुलम का उद्देश्य बच्चों में प्रारंभ से ही बिजनेस माइंडसेट विकसित करना, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से परिचित कराना और दक्ष बनाना है, ताकि वे समाज में केवल रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले व्यक्तित्व के रूप में उभरें। उन्होंने कहा कि साइंस ऑफ लिविंग पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व के हर पक्ष को निखारा जाएगा और उनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाया जाएगा।

कामकाजी महिलाओं के लिए 502 पालना घर सह क्रेच केंद्रों का उद्घाटन

पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को शुरू किए गए 'सेवा पखवाड़ा' के अंतर्गत गुरुवार को दिल्ली सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें कई योजनाओं का शुभारंभ भी शामिल था। इसी कड़ी में गुरुवार को सबसे पहले दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्थित दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 502 पालना घर सह क्रेच केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया।

दशकों के बाद ओबीसी वर्ग का नेता बना हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष

कांग्रेस आलाकमान ने राव नरेंद्र को बनाया प्रदेश अध्यक्ष

हरियाणा कांग्रेस ने इस बार प्रदेश संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए दशकों बाद ओबीसी वर्ग से राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बताया जाता है कि पिछले 20 साल से चले आ रहे दलित और जाट के समीकरण को बदलते हुए ओबीसी वर्ग से आने वाले किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। 48 साल बाद किसी अहीरवाल नेता को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। इससे पहले राव निहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। हालांकि जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो उस दौरान राव ओबीसी वर्ग में नहीं आते थे। वहीं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पार्टी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना है। इससे एक यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी के अंदर हुड्डा का दबदबा कायम है और वे अब भी कांग्रेस में (लगातार तीन विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद) अहमियत रखते हैं।

20 साल से बन रहा था दलित प्रदेश अध्यक्ष

कांग्रेस में पिछले 20 साल से दलित वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष बनते रहे हैं। 2001 से 2004 तक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष थे। उसके बाद कांग्रेस ने फूलचंद मुलाना, अशोक तंवर, कुमारी सैलजा और उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष चुना। मगर 2014 के बाद कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली। वहीं, दूसरी तरफ भाजपा ने गैर जाट वोट ओबीसी में डोरे डालते हुए उन्हें अपना मुख्य वोट बैंक बना लिया। पिछले तीन विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में ओबीसी वोट बैंक सबसे बड़ा निर्णायक साबित होता रहा है। इसलिए पार्टी ने इस बार अपने समीकरण में बदलाव करते हुए ओबीसी वर्ग के नेता राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष चुना।

तीन नामों में से राव नरेंद्र को चुना गया

राव नरेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे मुख्य विकल्प के तौर पर थे। ओबीसी में राव सबसे बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस हाईकमान ने पहले से ही मन बना लिया था कि प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए ओबीसी पर ही दांव लगाना है। मगर किसे बनाना है। इसके लिए पार्टी ने काफी मंथन किया और क्षेत्रीय समीकरण को भी ध्यान में रखा। हाईकमान के पास तीन नाम भेजे गए थे, जिनमें राव नरेंद्र के अलावा चिरंजीव राव और राव दान सिंह का नाम था।

राव दान सिंह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी हैं साथ ही उनके परिवार पर ईडी के मामले चल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने उनके नाम से परहेज किया। वहीं, चिरंजीव राव पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे हैं। अजय यादव समय–समय पर कांग्रेस आलाकमान को असहज स्थिति में डालते रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने चिरंजीव राव के मुकाबले राव नरेंद्र पर विश्वास जताया। वहीं, अहीरवाल बेल्ट हरियाणा कांग्रेस के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित होती रही है। 2024 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस यादव बहुल इलाके में 11 में से 10 सीटें हार गई थी। वहीं, राव नरेंद्र सिंह पर किसी गुट का ठप्पा नहीं है। कांग्रेस पिछले कई समय से गुटबाजी से जूझ रही है। ऐसे में उन्हें ऐसे नेता की जरूरत है, जो किसी गुट में शामिल नहीं रहा है। राव नरेंद्र सिंह राहुल गांधी के सामाजिक समीकरण में भी फिट बैठते हैं।

प्रदेश में कांग्रेस के पांच सांसद और 38 विधायक हैं

कांग्रेस के प्रदेश में पांच सांसद और 38 विधायक हैं। इनमें से चार सांसद और 32 विधायक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में हैं। इतना बड़े जनसमर्थन को हाइकमान अनदेखी नहीं कर सकता। हुड्डा के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। दूसरा बड़ा कारण जाट वोट बैंक है। हरियाणा में करीब 21 फीसदी वोट बैंक जाट बिरादरी का है। यह वोट बैंक एकतरफा हुड्डा के पीछे खड़ा है। दरअसल जाट वोट बैंक को आज भी भरोसा है कि भाजपा को यदि कोई हरा सकता है तो वे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। वहीं, कांग्रेस के पुराने नेता में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बचे हैं, बाकी पुराने कांग्रेसी पार्टी को छोड़ चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से पूर्व सीएम भजनलाल, पूर्व सीएम बंसीलाल, राव इंद्रजीत का परिवार शामिल रहा है। ये सभी भाजपा में हैं। वहीं, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी एक बार कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा चुके हैं। तीन बार सत्ता से बाहर रहने के बावजूद हुड्डा कांग्रेस में बने हुए हैं। यह पार्टी और उनके लिए भी काफी मायने रखती है। उधर, एक फैक्टर यह भी है कि कांग्रेस के भीतर संसाधन, धन और बल से पूर्व सीएम हुड्डा ही सबसे मजबूत नेता हैं। ऐसे में हुड्डा की अनदेखी करना पार्टी के लिए इतना आसान नहीं था।

.प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क.

किसानों के चेहरों की मुस्कान ही हमारी असली दीवाली : मोहन यादव

13 जिलों के किसानों को 653-34 करोड़ रुपये की राहत राशि सिंगल क्लिक से खातों में भेजी गई

श्वेतांक वर्मा
मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने बाढ़, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की हुई खराब फसल के लिए मुआवजा राशि को जारी कर किसानों को दिवाली का तौहफा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निव. ास स्थित समत्व भवन में किसानों को प्राकृतिक आपदा और कीट प्रकोप से हुई फसल क्षति की राहत राशि वितरण कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की सेवा ही भगवान की सेवा है। बाढ़ हो, आपदा हो, ओलाव. ृष्टि हो या कीट प्रकोप हो, किसान भा. ई हर विपदा से लड़ते और जूझते हैं। किसान पर कोई भी विपदा या आपदा आए सरकार संकट की हर घड़ी में सा. थी बनकर किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से कहा कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा परिवार बनकर हम आपके साथ हैं। आपकी खुशी में ही प्रदेश की खुशी है। उन्हा. ेने कहा कि हर प्रकार की आपदा और कीट प्रकोप से फसलों को हुई क्षति की राहत राशि किसानों को दी जाएगी। ये राहत राशि किसानों को बड़ा संबल देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जब तक आखिरी पीड़ित किसान को सहायता राशि नहीं मिल जाती, हमारी सरकार चौन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरों की मुस्कान ही हमारी असली दीपावली जैसी है। किसानों की मेहनत और जज्बा फिर से उनके खेतों को जीवन और समृद्धि से भर देगा।मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में किसानों को प्राकृतिक आपदा और कीट प्रकोप से हुई फसल क्षति की राहत राशि वितरण कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में बीते माहों में हुई अतिवृष्टि—बाढ़ और सोयाबीन में पीला मोजेक रोग से हुए फसल नुकसान के लिए 13 प्रभावित जिलों के 8 लाख 84 हजार 772 किसानों को 653.34 करोड़ की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि

इसमें अतिवृष्टि/बाढ़ से हुई फसल क्षति से प्रभावित 3 लाख 90 हजार 167 किसानों को 331.34 करोड़ रुपये एवं पीला मोजेक/कीट व्याधि से हुई फसल क्षति से प्रभावित 4 लाख 94 हजार 605 किसानों को 322 करोड़ रुपये की राहत राशि शामिल है।

किसानों की खोई मुस्कान लौटाना हमारी पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी पीड़ित किसान भाईयों को राहत राशि देने और फसल सर्वे के कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। किसानों के चेहरे की खोई मुस्कान लौटाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 6 लाख 69 हजार से अधिक धान उत्पादक किसानों के खाते में 337 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भी भावान्तर योजना शुरू की गई है। फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अन्तर की राशि सरकार सीधे किसानों को देगी। हम किसानों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों भाईयों के दुख–दर्द में हम आपके सेवक बनकर खड़े हैं। किसानों के माथे का पसीना बेकार नहीं जाएगा, आपकी मेहनत फिर से हरियाली का रूप लेकर प्रदेश को समृद्ध करेगी, हम सदैव आपके साथ हैं। राज्य सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है और उनके सुख–दुख में सहभागी है। हम प्रदेश के किसी भी किसान को आपदा में अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025–26 में अब तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को विभिन्न मदों में कुल 229 करोड़ 45 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। गत माह 6 सितंबर को ही फसल क्षति के लिए 11 जिलों के 17 हजार से अधिक किसानों को 20 करोड़ से अधिक की राहत राशि दी थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार द्वारा सोयाबीन में पीले मोजेक रोग से फसल प्रभावित किसानों को राहत राशि दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने दीपावली से पहले ही हमारी दीपावली मनवा दी : किसान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राहत राशि वितरण के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ित किसानों से आत्मीय संवाद भी किया। संवाद के दौरान किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दशहरा एवं भव्य शस्त्र पूजन के आयोजनों एवं सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन किया। किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दीपावली से पहले ही हमारी दीपावली मनवा दी। हमें यह महसूस हो रहा है कि सरकार हमारे साथ है। पीला मोजेक की राहत राशि हमें पहली बार मिली। यह सच्चे अर्थों में किसान हितैषी सरकार है। उत्साहित किसानों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राहत राशि मिलने से दशहरे पर ही किसानों की दीपावली हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुरहानपुर जिले के किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि केला आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

सोयाबीन उत्पादक किसानों को फसल बेचने में नहीं करना पड़ेगा परेशानी का सामना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राहत राशि मिलने पर सभी किसानों को बधाई देते हुए कहा कि आज से ही सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत पंजीयन प्रारंभ हो गया है। अब किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोयाबीन मंडी में बेचें, यदि एमएसपी से कम राशि में फसल बिकती है, तो बेची गई फसल की कीमत और एमएसपी के अंतर की राशि यानि भावांतर की राशि अगले 15 दिनों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए किसानों को इस साल सोयाबीन का अत्यधिक भाव मिलेगा। इस बार सोयाबीन की एमएसपी 500 रुपए से अधिक बढ़कर 5328 रुपए हो गई है। केंद्र सरकार ने गेहूं की फसल के लिए फिर से एमएसपी बढ़ाई है। यह राज्य सरकार के किसानों की समृद्धि के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लाभकारी रहेगा।

रतलाम जिले को दी गई 213.04 करोड़ रुपए की राहत राशि

रतलाम जिले के किसानों को कुल 213.04 करोड़ रुपए की राहत राशि दी गई है। यहां के किसान श्री भरतलाल जाट और श्री प्रहलाद पाटीदार ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण उनकी सोयाबीन फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। उनके पास अगली फसल के लिए खाद और बीज खरीदने तक के लिए पैसा नहीं था लेकिन सरकार की राहत राशि मिलने से अब यह संकट खत्म हो गया है। जिले के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि आगामी 10 अक्टूबर को रतलाम में किसान

सम्मेलन आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे स्वयं किसानों के बीच आयेंगे। नीमच जिले को अतिवृष्टि से सोयाबीन फसल को हुए नुकसान के लिए 119.06 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि दी गई। किसान राकेश पाटीदार और शंभुलाल अहीर ने कहा कि दशहरा और दीवाली के अवसर पर फसल की मुआवजा राशि मिलने से किसानों के सामने खाद–बीज खरीदने का संकट खत्म हो गया है। मंदसौर जिले के सोया. बीन उत्पादक किसानों को कुल 267.30 करोड़ रूपए राहत राशि अंतरित की गई है। यहां के किसान लाल दास बैरागी, रेखाबाई, ओमप्रकाश, सुनीता शर्मा ने कहा कि मुआवजा राशि पाकर किसानों की दीपावली से पहले ही दीपावली मन गई है। उज्जैन जिले के किसानों को 44 लाख रुपए राहत राशि मिली है। किसान श्री पवन सिंह और श्री उदय सिंह ने कहा कि सरकार ने फसल कटने से पहले ही मुआवजा राशि दे दी है। भावांतर योजना में पंजीयन कराने के लिए यहां के किसान उत्साहित हैं। विदिशा जिले के किसानों को 62 लाख रूपए दिए गए हैं। किसान श्री भारत सिंह और श्री मनोज कुमार ने कहा कि भारी बारिश से फसल खराब हो गयी थी, सरकार ने मुआवजा देकर बड़ी मदद की है।

केला किसानों को प्रति हेक्टेयर 2 लाख की राहत राशि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बु. रहानपुर जिले के केला उत्पादक अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को 3.39 करोड़ रूपए मुआवजा राशि दी गई है। किसान श्री पांडुरंग बिट्ठल और विनोद पुंडलिक ने कहा कि यहां के केला उत्प. ादक किसानों को लगभग 2 लाख प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जा रहा है और इससे बड़ी राहत हो गई है। शह. डोल जिले के सोयाबीन उत्पादक पीला मोजेक प्रभावित 8935 किसानों को 6.36 करोड़ रूपए मुआवजा राशि मिली है। किसान श्री राजेन्द्र द्विवेदी और श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया। खंडवा जिले के सोयाबीन उत्पादक किसानों को अतिवृष्टि और पीला मोजेक की राहत के रूप में 55 लाख रूपए मिले हैं। किसान श्री कन्हैयालाल और श्री किशोर ने कहा कि आपदा में सरक. ार हमारा संबल बनी है। पीला मोजैक से हुए नुकसान की उन्हें पहली बार भरपाई की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खंडवा जिले में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया। बड़वानी जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित 662 किसानों को 37 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर वे 6 अक्टूबर को बड़वानी का दौरा कर नशा मुक्ति अभि. ियान में सहभागिता करेंगे। किसान श्री पुष्पेन्द्र और श्री सालकराम ने कहा कि मुआवजा पाकर वे और उनका परिवार बेहद हर्षित है। दमोह जिले के मक्का उत्पादक अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को 56 लाख रुपए की राहत राशि मिली है। यहां के किसान रविदास और भग. वानदास ने कहा कि भावांतर योजना के पंजीयन को लेकर दमोह जिले के किसानों में बेहद उत्साह है। अलीराजपुर जिले के सोयाबीन उत्पादक किसानों को पीला मोजेक से हुए फसल नुकसान के लिए 41.55 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी गई इससे 49 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं। किसान श्री वेस्ता और श्री कालू ने मुआवजा मिलने पर हर्ष जताया। मंडला जिले के धान और मक्का उत्पादक अतिवृष्टि प्रभावित किसानों की फसल को हुए नुकसान के लिए 53 हजार रुपए मुआवजा राशि मिली है। किसान श्री चंदर सिंह और श्री देव. ीलाल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि धान उत्पादक किसानों को पहले ही बोनस मिलने से यहां उत्साह का वातावरण है।

मकान ढहने वाले किसान को मिली 92 हजार रुपए की राहत राशि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिवनी जिले के जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की। बताया गया कि यहां मकान ढहने से प्रभावित एक किसान को 92 हजार रुपए की राहत राशि मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राहत राशि पाने वाले सभी किसानों से कहा कि शेष प्रभावित जिलों के किसान निराश न हो, वहां अभी सर्वे चल रहा है और सर्वे पूरा होते ही राहत राशि दी जाएगी। राहत राशि वितरण कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, आयुक्त राजस्व अनुभा श्रीवास्तव सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

पूर्वोत्तर के निवेशकों के लिए प्रदेश बनेगा विकास और अपार अवसरों का केंद्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संकल्पबद्धता मध्य प्रदेश को देश के हर राज्य के निवेशक के लिए सु. रक्षित, पारदर्शी और अनंत अवसरों का केंद्र बना रही है। मध्य प्रदेश में निवेशकों को अब व्यापार के अवसर के साथ ही स्थायी विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति का भी भरोसा मिलता है। मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थि. ति, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और बा. जार तक आसान पहुंच इसे निवेशकों के लिए एक अनूठा केंद्र बनाती है। मध्यप्रदेश ने उद्योग–अनुकूल नीतियां और क्लस्टर आधारित विकास मॉडल तैयार किए हैं, जिससे निवेशक अपनी नए उद्योग की योजना को तेजी से क्रियान्वित कर सकते हैं। राज्य के एग्रो और फूड प्रोसेसिंग से. क्टर में निवेशकों को कृषि उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षमताओं का लाभ मिलता है। टेक्सटाइल्स और अपैरल सेक्टर राज्य की परंपरागत और आधुनिक क्षमता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे निर्यात और रोजगार दोनों में वृद्धि संभव होती है। फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में मध्यप्रदेश की ताकत निवेशकों को कच्चे माल, अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन के अवसर प्रदान करती है। सीमेंट, मिनरल्स और इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स, टूरिज्म और वेलनेस, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी इक्विपमेंट तथा प्लास्टिक्स और पॉलिमर्स जैसे सेक्टर राज्य को निवेश के लिए बहुआयामी विकल्प प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल से इन सेक्टरों में निवेश केवल व्यवसाय का निर्णय नहीं बल्कि आर्थिक विकास और स्थायी अवसरों का रास्ता बन रहा है।

कर्नाटक के जंगल मिली रूसी महिला की बेटियों का पिता पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

''सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब उसकी बेटियां और उनकी रूसी मां कर्नाटक के जंगल में गुफा में रह रही थीं, तब वह गोवा में क्या कर रहा था? कोर्ट ने पूछा कि क्या उसके पास भ.ारत में रहने के वैध दस्तावेज हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की, जब बिजनेसमैन ने अपनी दो बेटियों की कस्टडी मांगी और उन्हें रूस भेजने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की''

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 6 अक्टूबर को एक इजरायली नाग. रिक की याचिका खारिज कर दी। ये इजरायली खुद को एक रूसी महिला की दो बच्चियों का पिता बता रहा था। ये महिला और उसकी दो बेटियां कर्नाटक के गोकर्णा इलाके की एक गुफा में मिली थीं। कोर्ट ने साफ कहा कि यह याचिका 'पब्लिसिटी के लिए' दाखिल की गई लगती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने महिला और बच्चों को वापस रूस भेजने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि महिला खुद रूसी दूतावास को चिट्ठी लिखकर अपने देश लौटने की बात कह चुकी थी। गोवा में रह रहा इजरायली नागरिक डॉर शालोम गोल्डस्टीन ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि वही बच्चियों का पिता है। वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। हाई कोर्ट में उसने कहा था कि मां और बच्चियों को डिपोर्ट करना बच्चों के अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। गोल्डस्टीन हाई कोर्ट को ये बताने में नाकाम रहा कि अगर वो महिला और बच्चों का भरण–पोषण कर रहा था, तो वे गुफा में क्यों रह रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट में भी यही सवाल दोहराया गया। जस्टिस बागची ने पूछा कि जब आपका बच्चा गुफा में था तो आपने क्या किया। कोर्ट ने गोल्डस्टीन की मंशा पर भी सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप इजरायली हैं। भारत में आपकी क्या दिलचस्पी है। आप नेपाल जाते हैं, वीजा रिन्यू कराते हैं और फिर गोवा वापस आते हैं। आपकी कमाई का जरिया क्या है? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या कोई आधिकारिक दस्तावेज है जो साबित करता हो कि वो सच में बच्चियों का पिता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कृपया दिखाइए कि आपको आधि ाकारिक रूप से पिता घोषित किया गया है. हम क्यों ना आपको भी डिपोर्ट करने का आदेश दें। आप इसी देश में बैठे हैं। आखिर में कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमें यह याचिका पूरी तरह फिजूल लगती है। जाहिर है, याचिका. कर्ता ने पब्लिसिटी या किसी और मकसद से हाई कोर्ट के साथ–साथ इस कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। खारिज। इसके बाद गोल्डस्टीन ने याचिका वापस लेने की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने मान लिया। जाते–जाते जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि यह देश सबके लिए स्वर्ग बन गया है। जो भी आता है, यहीं का होकर रह जाता है।उल्लेखनीय है कि जुलाई, 2025 में महिला और उसकी दो बेटियो को गोकर्णा के रामतीर्थ हिल्स में एक गुफा में रहते हुए पाया गया था।

उनके पास कोई वैध ट्रैवल डॉक्युमेंट नहीं था। पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू करके फॉरेनर्स रेस्ट्रिक्शंस सेंटर की निगरानी में तुमकुरु के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस भेज दिया था। इसके बाद रूस दूतावास ने रूस लौटने के लिए उन्हें इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्युमेंट जारी कर दिए।

9 जुलाई को पुलिस ने बचाया था रूसी महिला और उसकी दो बेटियों को

कर्नाटक के गोकर्ण के पास रामतीर्थ पह. ाड़ियों की एक गुफा में रूसी महिला नीना कुटीना और उसकी दो बेटियों को 9 जुलाई को पुलिस ने बचाया था। 2017 में वीजा खत्म होने के बाद से नीना कुटीना भारत में अवैध रूप से रह रही थी और आध्यात्मिक शांति की तलाश में अपनी बेटियों के साथ जंगल में रह रही थी। बच्चों को एक महिला स्वागत केंद्र में ले जाया गया, और रूसी दूतावास से संपर्क किया गया ताकि उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सके।

घटना का विवरण

9 जुलाई को कर्नाटक पुलिस गश्त पर थी, तभी उन्हें गोकर्ण के पास रामती. र्थ पहाड़ियों में एक गुफा मिली। गुफा में नीना कुटीना और उसकी दो नाबा. लिग बेटियों को पाया गया। महिला की पहचान 40 वर्षीय नीना कुटीना उर्फ मोही के रूप में हुई। वह हिंदू दर्शन और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से प्रभावित थी और आध्यात्मिक शांति की तलाश में गोवा से गोकर्ण आई थी।

कानूनी स्थिति

नीना कुटीना का बिजनेस वीजा अप्रैल 2017 में खत्म हो गया था और वह 8 सितंबर 2018 से भारत में अवैध रूप से रह रही थी। पुलिस ने गुफा की तलाशी ली, जहां उन्होंने नीना कुटीना और उनकी बेटियों को पाया। सुरक्षा और जोखिम भरे माहौल को देखते हुए, महिला और बच्चों को करवार के महिला स्वागत केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया।रूसी दूतावास से संपर्क किया गया और उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू की गई।

बच्चों का मामला और हाई कोर्ट

नीना कुटीना की बेटियों के भारत में पैदा होने के कारण, कर्नाटक हाई कोर्ट ने महिला को वापस भेजने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी ताकि बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखा जा सके। नीना कुटीना और उसकी बेटियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, और उनकी वापसी के लिए आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही थी।

.प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

उ.बंगाल में आयी बाढ़ मानव जनित, डीवीसी मनमर्जी से पानी छोड़ रहा : ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उत्तर बंगाल में आई बाढ़ और उसके कारण हुए विनाश को मानव जनित बताया तथा डीवीसी पर पानी को अनियंत्रित रूप से छोड़ने का आरोप लगाया जिसके परिणामस्वरूप राज्य के दक्षिणी हिस्सों में नदियां उफान पर हैं। ममता ने बाढ़ और भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही शोक संतप्त परिवारों के एक सदस्य को होमगार्ड की नौकरी देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमें अब तक उत्तर बंगाल में आई बाढ़ में 23 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। इस क्षेत्र में शनिवार रात और रविवार तड़के 12 घंटे से ज्यादा समय तक 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण करने के लिए बाग. डोगरा रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रही थीं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटों से राज्य के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग के दुआर का नाग. राकाटा और मिरिक क्षेत्र भूस्खलन और आवासीय संपत्तियों के बह जाने से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। ममता ने कहा कि परसों रात से ही मुख्य सचिव, डीजीपी और मैं उत्तर बंगाल की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उत्तर बंगाल में... 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई, जो लगातार 12 घंटे तक जारी रही। फिर, भूटान से पानी संकोश (नदी) के जरिए बहकर आया और सिक्किम का पानी कई इलाकों में भर गया। उन्होंने खतरे के निशान के करीब बह रही हुगली नदी की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश से पानी फरक्का से छोड़ा जा रहा है, जिससे बंगाल की नदियां खतरे की स्थिति में पहुंच गई हैं। ममता ने आरोप लगाया कि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) अपनी इच्छानुसार पानी छोड़ रहा है। मैथन और पंचेत बांधों से गाद निकालने का काम न होने से उनकी जल धारण क्षमता में काफी कमी आई है। डीवीसी झारखंड को बाढ़ से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है और बंगाल इसका खमियाजा भुगत रहा है। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि झारखंड को बचाना जरूरी है। लेकिन पिछले दो दशकों से गाद निकालने की मांग करते–करते हमारा गला रुंध गया है।श्श उन्होंने कहा कि बांधों की क्या जरूरत है? पानी अपने प्राकृतिक रास्ते से बह सकता था और प्राकृतिक रूप से निकल भी सकता था। तब सभी राज्य बराबर–बराबर असर झेल सकते थे। लेकिन बंगाल ही इसका शिकार हो रहा है। पानी दुर्गापुर और फरक्का बैराजों से छोड़ा जा रहा है और हमारी सड़कें व पुल बह रहे हैं। ममता ने कहा कि उन्हें

रविवार को भूटान सरकार से सहानुभूति व्यक्त करते हुए एक पत्र मिला है।

उन्होंने कहा कि हमने उनसे धीरे–धीरे पानी छोड़ने का अनुरोध किया था क्योंकि एक बार पानी छोड़ने के बाद, इसे हम तक पहुंचने में 2–3 दिन लगते हैं। फिर भी उन्होंने जितना पानी छोड़ा, उससे नागराकाटा, धूपगुड़ी और जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, माटीगाड़ा, दार्जिलिंग और मिरिक के कई इलाके बह गए। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके नागराकाटा और मिरिक के साथ–साथ जोरेबंगला और कलिम्पोंग हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई पर्यटकों को पहले ही बचा लिया गया है, हालांकि डायमंड हा. र्बर का एक व्यक्ति अब भी लापता है। उन्होंने कहा कि हम आज इस क्षेत्र से लगभग 500 पर्यटकों को वापस लाएंग. े। हम 45 वोल्वो बसों और उत्तर बंग. ाल राज्य परिवहन निगम की बसों का उपयोग कर रहे हैं, और सिलीग. ुड़ी में अन्य पर्यटकों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने होटलों को निर्देश दिए हैं कि वे फंसे हुए पर्यटकों को न निकालें।

सभी पर्यटकों को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी

ममता ने कहा कि वह मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ सबसे पहले हाशिमारा पहुंचेंगी और फिर बाढ़ प्रभावित नागराकाटा क्षेत्र का रुख करेंगी। मंगलवार को वह मिरिक के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी। उन्होंने कहा कि डीजीपी पहले ही उत्तर बंगाल पहुंच चुके हैं। मैंने मंत्री अरूप बिस्वास और सिलीगुड़ी के महापौर गौतम देब को राहत कार्यों का निरीक्षण करने के लिए धूपगुड़ी पहुंचने को कहा है।

केंद्र ने बाढ़ राहत उपायों के लिए धन मुहैया नहीं कराया

ममता ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने बाढ़ राहत उपायों के लिए धन मुहैया नहीं कराया है और राज्य सरकार ''किसी तरहश्श अपने दम पर स्थिति से निपट रही है। उन्होंने कहा कि वे वोटों में हेराफेरी करने, चुनाव आयोग को राजनीतिक रूप से प्रभावित करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते है। उन्होंने बाढ़, सड़क, आवास, हर चीज के लिए बंगाल की निधि को रोक दिया है। भले ही जीएसटी लागू किया गया, जिसका हमने लोगों के लिए समर्थन किया था, हमें 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

केंद्र पर हमारा 1.85 लाख करोड़ रुपये बकाया

उन्होंने कहा कि केंद्र पर हमारा 1.85 लाख करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 20,000 करोड़ रुपये और जोड़ दीजिए। हम पैसा कहां से लाएंगे?श्श अगले 48 घंटों में राज्य की नदियों में पानी बढ़ने की चेतावनी देते हुए ममता ने कहा कि डीवीसी द्वारा पंचेत और मैथन से पानी छोड़े जाने के कारणश्श पूर्वी मिदनापुर के घाटल में एक बार फिर जलभराव हो गया है, जो कि एक निचला इलाका है।

दार्जिलिंग-जलपाईगुड़ी में लैंडस्लाइ. ड-बाढ़ से मरने वालों की संख्या 28 पार

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुए भयानक भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, जबकि छह लोग अभी तक लापता हैं। बचाव दल पहाड़ी इलाकों में बढ़ते पानी से जूझ रहे हैं। इस आपदा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच राजनी. तिक जंग को और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को इस मानव निर्मित आपदा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर जलपाईगुड़ी में आपदा प्रभावित नागराकाटा क्षेत्र का दौरा करने के दौरान उसके सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। दरअसल क्षेत्र में 12 घंटों में 300 मिमी से अधिक बारिश के कारण भूस्खलन से दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग जिलों में भारी तबाही मची। इससे हजारों पर्यटक फंस गए। सैकड़ों लोग बेघर हो गए और कई पहाड़ी ढलानें धंस गईं। बचाव दल को 40 से अधिक भूस्खलन स्थलों को साफ करने में कठिनाई हो रही है। क्योंकि उफनती नदियों और टूटे हुए पुलों के कारण दूरदराज की बस्तियों का संपर्क टूट गया है। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि राहत अभियान अभी जारी है। उन्होंने कहा कि अभी तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और छह लापता है। ये मौतें दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी दोनों जिलों में हुई हैं।

.प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

कमाई के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स का हिस्सा बन रहे झुग्गियों में रहने वाले लोग

एक क्लिनिकल ट्रायल्स में हो जाती है 50 हजार तक कमाई, हालांकि कुछ परीक्षणों में रोजाना भी 500 से 1000 हजार रुपए दिए जाते हैं।

गुजरात (अहमदाबाद)। अहमदाबाद की झुग्गियों में रहने वाले लोग अपना घर चलाने और बच्चों की शादी कराने के लिए क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बन रहे हैं। अगर क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल या नैदानिक परीक्षण एक प्रकार का शोध अध्ययन है जिसमें मनुष्यों पर नए उपचारों, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों या जीवनशैली में बदलाव की सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाता है। इन परीक्षणों को कई चरणों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई उपचार सुरक्षित है और वास्तव में काम करता है। क्लिनिकल ट्रायल किसी भी नई चिकित्सा को प्रयोगशाला से मरीजों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हाल ही गुजरात के अहमदाबाद की झुग्गियों में रहने वाली नूरजहां हाल ही में एक क्लिनिकल परीक्षण से वापस लौटी हैं। उन्होंने एक रिसर्च लैबोरेटरी में तीन दिन बिताए थे। वहां जांचकर्ताओं और दवा कंपनियों ने उन पर नई दवाओं का परीक्षण किया था।अपने छोटे से घर में जब नूरजहां दाखिल हुईं तो उनके बच्चे और पति उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे।नूरजहां के घर में एक छोटा–सा रसोईघर, पार्टिशन वाला पलंग और कपड़ों से भरे कुछ बक्से हैं। नूरजहां अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही हैं। परिवार के भरण–पोषण और बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा करने के लिए नूरजहां क्लिनिकल ट्रायल्स में शामिल होती हैं। उनका कहना है कि मैं यह सुनिश्चित करती हूं कि मेरे बच्चे रात में भूखे न सोएं।

नूरजहां की दुनिया और क्लिनिकल ट्रायल

नूरजहाँ इस समय तीन महीने के क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा हैं। उन्हें नियमित रूप से परीक्षणों के लिए रिसर्च लैब जाना होगा। क्लिनिकल ट्रायल के अंत में उन्हें 51 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। नूरजहाँ से बात की, तब तक उन्हें 15 हजार रुपये मिल चुके थे। नूरजहाँ ने बताया कि वह बाकी 36 हजार रुपये अपनी बेटी की शादी में खर्च करेंगी। नूरजहां ने बताया कि हम गरीब लोग हैं। हमें तो वैसे भी इसी छोटी सी झोपड़ी में मरना है। मुझे गर्व है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। जब मुझे बाकी पैसे मिल जाएँगे, तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँगी। नूरजहाँ अहमद. ाबाद में साबरमती नदी के किनारे से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए बसाई गई बस्ती गणेश नगर में रहती हैं। वे आस–पास की रिसर्च लैब्स में चल रहे क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने वाले सैकड़ों लोगों में से एक हैं। नूरजहां की तरह 60 साल की जस्सीबेन चुनारा भी क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लेती हैं। कुछ साल पहले उनके पति और बेटे दोनों की मौत हो गई थी। पहले वे अहमदाबाद

क्लिनिकल ट्रायल से कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो मैंने इसमें शामिल होना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह कई ट्रायल्स में हिस्सा ले चुकी हैं। गणेशनगर के स्थानीय लोग इन क्लिनिकल ट्रायल्स को 'एसटीडी' कहते हैं। दरअसल इन्होंने 'स्टडी' शब्द को अपना नाम दे दिया है। बिस्मिल्लाह ने बताया कि मैं कम से कम सात से दस एसटीडी का हिस्सा रही हूं और 12 हजार से 15 हजार रुपये कमाए हैं। मुझे तीन दिन तक लैबोरेटरी में रहना पड़ता है और दवा लेने के बाद वे नियमित रूप से मेरा खून लेते रहते हैं।

के जमालपुर की सब्जी और फूल मार्केट के पास रहती थीं। जस्सीबेन ने कहा कि जब मैं जमालपुर में रहती थी, तब कभी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मार्केट से बेकार सब्जियां उठा लेती थी और उन्हें बेच देती थी। उन्होंने आगे कहा कि अब गणेशनगर शिफ्ट हा. ेने के बाद मेरे पास कोई आय का साध् ान नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल में शा. मिल होने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। उनकी छोटी झोपड़ी में फर्नीचर के नाम पर केवल एक खाट है। जस्सीबेन चुनारा ने बताया, अब मैं सब्जियां नहीं बेच सकती। मैं बीमार हूं। शरीर में जलन होती है। हाथा. ें में दर्द रहता है। फिर भी मैं क्लि. निकल ट्रायल में जाती हूं ताकि भूखी न मरना पड़े। अहमदाबाद के बाहर पीराना डंपिंग यार्ड के पास बसे गणेशनगर में करीब 15 हजार लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर परिवार कम आय वाले हैं। इनमें से कई लोग पहले सुभाष ब्रिज, शाहपुर, शंकर भवन, वीएस अस्पताल, वासणा बैराज और जमालपुर जैसे नदी किनारे के इलाकों में रहते थे और अहमदाबाद की मंडियों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे।जबकि महिलाएं मार्केट में या किसी के घर में काम करती थीं और रोजाना 200 से 400 रुपये तक कमाती थीं। पुनर्वास के बाद इनमें से कई लोगों ने अपना काम खो दिया है।

बिस्मिल्लाह की कहानी

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, सुभाषब्रिज से वासणा बैराज तक नदी किनारे के इलाके में रहने वाले 12 हजार से अधिक परिवारों को 29 सरकारी कॉलोनियों में शिफ्ट किया गया है। विस्थापितों को उनके पुराने घर से दो–तीन किलोमीटर दूर ही नए मकान देने का वादा किया गया था। 48 साल की बिस्मिल्लाह कोला का गणेशनगर आने से पहले ही उनका तलाक हो चुका था। एक समय वे घरेलू सहायक के तौर पर काम करती थीं और पास की सोसायटियों में उन्हें काम मिल जाता था। लेकिन बेटे की आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद बिस्मिल्लाह ने क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अकेली हूं। मेरा सहारा कोई नहीं है। अदालत में बेटे का केस लड़ने के पैसे नहीं हैं। घर की मरम्मत कराने के पैसे भी नहीं हैं। मैं क्या करूं? किसी ने बताया कि

एजेंट ढूढ़ते हैं लोगों को

बिस्मिल्लाह को इस क्लिनिकल ट्रायल के बारे में स्थानीय एजेंटों के नेटवर्क से पता चला। एजेंट जितने लोग लाते हैं, उनके लिए उन्हें प्रति व्यक्ति 500 से 1,000 रुपए तक मिलता है। एक एजेंट ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि आमतौर पर लैब्स हमसे संपर्क करती हैं, जब उन्हें किसी खास आयु वर्ग या महिलाध्पुरुष की जरूरत होती है। उनके पास हमारे नंबर होते हैं और वे हमें कॉल करते हैं। हम एक व्हाट्सऐप ग्रुप में हैं, जहाँ विज्ञापन पोस्ट किए जाते हैं। कभ ी–कभी हम लोगों को लैब में लेकर जाते हैं, कभी उन्हें सीधे भेजते हैं।यह एजेंट पहले खुद भी ट्रायल्स में भाग लेते थे। अब वे बिस्मिल्लाह, नूरजहाँ और जस्स. ीबेन जैसे लोगों का नेटवर्क चलाते हैं। एजेंट के अनुसार, इसमें गलत क्या है? (रिसर्च कंपनियाँ) कुछ भी गैरकानूनी नहीं कर रही हैं। वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करती हैं। लोगों की सहमति लिखित

रूप में और कैमरे पर ली जाती है। प्रतिभागियों को बताया जाता है कि दवा और उसके दुष्प्रभावों का ट्रायल किया जा रहा है। डॉक्टर का नाम और फोन नंबर भी दिया जाता है, ताकि ट्रायल में शामिल होने वाले घर लौटने के बाद भी डॉक्टर से मदद ले सकें।

पैसे कमाने की लालत ने लोगों ने इसे बना लिया व्यवसाय

स्थानीय कार्यकर्ता बीना जाधव ने कहा कि पहले एक–दो बार ये लोग पैसे कमाने के लिए ट्रायल्स में शामिल हुए थे, लेकिन अब यह एक व्यवसाय बन गया है। हम उन्हें जोखिमों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि इस इलाके में कोई रोजगार नहीं है। एक प्रमुख रिसर्च लैब से संपर्क किया कि क्या ये ट्रायल्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन और भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के अनुसार किए

की गाइडलाइन कहती है कि मेडिकल ट्रायल में भाग लेने के लिए पैसे पाने वाले लोगों के लिए, इस तरह के पैसे को आम तौर पर स्टडी के लाभ के बजाय भर्ती प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि, आईईसी दृ आईआ. रबी को भुगतान की राशि और उसकी प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके पीछे किसी तरह की मजबूरी या गलत वजह न हो। पैसों का भुगतान इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि लोगों को इसमें शामिल होने या स्टडी में बने रहने के लिए अनावश्यक तौर पर प्रोत्साहित किया जाए।

वकील ने इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन बताया

सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय पारिख ने इस तरीके को मानवाधिकार का गंभ. ीर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो

उनकी सहमति को कानूनी रूप से सू. चित सहमति नहीं माना जा सकता। मध्य प्रदेश स्थित ‘स्वास्थ्य अधिकार मंच’ नामक संगठन द्वारा दायर एक याचिका का संजय पारिख अदालत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस संगठन ने इंदौर में क्लिनिकल ट्रायल्स से जुड़ी कई मौतों के बाद चिंता व्यक्त की थी। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अमूल्य निधि ने कहा, ऐसा सिर्फ गुजरात में नहीं हो रहा है। मुंबई, हैदराबाद और अन्य शहरों में भी लैब्स लोगों का इस्तेमाल गिनी पिग्स की तरह कर रही हैं। परीक्षणों में अनियमितताओं की जांच कर चुकी एक संसदीय समिति ने भी देश के कम. जोर वर्गों के लिए गिनी पिग शब्द का इस्तेमाल किया था। संजय पारिख ने आगे कहा कि वॉलंटियर्स की भर्ती से लेकर ट्रायल के रिजल्ट तक हर चरण की निगरानी के लिए उचित व्यवस्था नहीं बनाई गई है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कमजोर लोगों का शोषण होता रहेगा। ट्रायल के निश्चित निष्कर्षों को छोड़कर बाकी सारी जानकारी सार्व. जनिक की जानी चाहिए।समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिका स्थित ग्रैंडव्यू रिसर्च के हवाले से बताया कि भारत का क्लि. निकल ट्रायल बाजार 2025 तक 1.51 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। कंप. नियाँ भारत की ओर इसलिए आकर्षित हो रही हैं क्योंकि यहाँ ट्रायल के फेल होने की लागत कम होती है। कॉमनवेल्थ फार्मास्युटिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राव वीएसवी वडलामुडी ने बी. बीसी से कहा कि एक तरफ लोगों को पैसों की जरूरत है और दूसरी तरफ कंपनियों को दवाओं के परीक्षण के लिए वॉलंटियर्स की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि यह सब कानून और सरकारी मानकों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।ऐसे सवाल पूछकर हम किसे बचा रहे हैं, यह भी मैं नहीं जानता। दवा बनाना एक सम्मानजनक व्यवसाय है और हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है ताकि समाज को बड़े पैमाने पर लाभ मिल सके, लेकिन सभी मानकों का पालन होना चाहिए।

courtesy-www.bbc.com

बरेली में बवाल: पथराव-फायरिंग में 22 पुलिसकर्मी घायल, 39 आरोपी हिरासत में, आठ गिरफ्तार

बरेली। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद करीब तीन घंटे तक बवाल हुआ। शहर के अलग–अलग इलाकों में भीड़ जुटी। बेकाबू हुई भीड़ ने पथराव और फायरिंग की। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कुछ लोगों के भी घायल होने की खबर है। पुलिस ने अब तक 39 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आठ की गिरफ्तारी हुई है।

बरेली में आई लव मोहम्मद के समर्थन में इत्तेहाद–ए–मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के बुलावे पर शुक्रवार को जुटी भीड़ मौलाना के नदारद रहने से अराजक हो गई। बवालियों ने खलील स्कूल तिराहे के पास दुकानों व वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। नावल्टी चौराहा पर पुलिस टीम पर पथराव और श्यामगंज में फायरिंग की। डीआईजी अजय कुमार साहनी के मुताबिक, इसमें 22 पुलिस. कर्मी घायल हुए हैं। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। लाठीचार्ज भी किया। डीआईजी ने कहा कि शाम पांच बजे स्थति काबू में आई। पुलिस ने 39 लोगों को हिरासत में लिया है। आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मौलाना ने 19 सितंबर को किया था एलान

आई लव मोहम्मद के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा में 19 सितंबर को एलान किया था कि शुक्रवार को वह इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में विरोध–प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद कलक्ट्रेट जाकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे। इसके लिए पुलिस–प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी थी। बृहस्पतिवार रात 12 बजे अधिकारियों ने आईएमसी की ओर से जारी पत्र को सार्वजनिक किया था। इसमें कार्यक्रम स्थगित किए जाने की जानकारी दी गई थी। वहीं, शुक्रवार सुबह मौलाना तौकीर ने वीडियो जारी कर रात में जारी पत्र को फर्जी बताया। दावा किया कि विरोध–प्रदर्शन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप ही होगा। उनके बुलावे पर शहर में भीड़ जुटी, पर अपराह्न साढ़े तीन बजे तक मौलाना का कोई पता न चला। तब मौलाना के समर्थकों ने

हंगामा शुरू कर दिया।

डॉक्टर की दुकान के शीशे तोड़े

नौमहला मस्जिद पर हंगामा व नारेबाजी शुरू हुई तो डीआईजी अजय साहनी व एसपी सिटी मानुष पारीक वहां पहुंचे। उनके समझाने पर भीड़ वहां से हटी तो बिहारीपुर में खलील स्कूल तिराहे के पास स्थिति बेक. ाबू हो गई। उग्र युवकों ने एक डॉक्टर की दुकान के शीशे और बाहर खड़ी दो बाइकें तोड़ दीं। भीड़ को हावी होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद शाम पांच बजे तक जगह–जगह उपद्रवियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प होती रही।

पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर खदेड़ा

इससे पहले श्यामगंज में भी भीड़ बेकाबू हो गई। पथराव और फायरिंग की नौबत आई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। नावल्टी चौराहा पर आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा गया। एसएसपी ने खुद माइक संभाला। लोगों से घर जाने की अपील की। पुलिस शहर में बवाल भड़काने के लिए मौलाना व उनके सहयोगियों पर कानूनी शिकंजा कसने की रूपरेखा बना रही है।

बवाल से प्रभावित इलाके

बिहारीपुर, श्यामवंग, कुतुबखाना, इस्ल. ामिया मार्केट, मैलानी मार्केट, कोहाड़ापौर, आलमगिरीगंज, बांस भांडी, सिविल स्वयंस, साहूकारा और पुराना बस अड्डा।

बवाल में कुछ लोगों के घायल होने की आशंका

कुछ लोगों के घायल होने की आशंका है लेकिन उनकी संख्या के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि तस्वीरों में टूटे हुए शीशे बिखरे हुए जूते और सड़कों पर पत्थर पड़े थे।

इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान जाने पर अड़ी थी भीड़

जैसे ही भीड़ ने इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान की और मार्च करने का प्रयास किया, पुलिस ने उन्हें खलील तिराहा पर रोकने की कोशिश की। इसके कारण प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।

डीएम अविनाश सिंह

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हम लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रहे हैं।

एफआईआर दर्ज की जाएगी

डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। जिस तरह से भीड़ बैनर लेकर निकली और पथराव किया उससे एक सुनियोजित साजिश का संकेत मिलता है। घटना के वीडियो और तस्वीरों के आधार पर इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आईएमसी के प्रवक्ता ने हाथ काटने की दी थी धमकी

21 सितंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें आईएमसी के प्रवक्ता डॉ. नफीस ने किसा इंस्पेक्टर का हाथ काटने की धमकी दी थी। दरअसल, पुलिस किला बाजार से आई लव मोहम्मद के पोस्टर हटवाने गई थी। इसे लेकर डॉ. नफीस ने अपने समर्थकों के बीच कहा था कि इंस्पेक्टर किला से उनकी बात हुई है। उनसे कहा है कि पोस्टर हटाने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे और वर्दियां उतरवा दी जाएंगी। वीडियो वायरल होने पर डॉ. नफीस पर केस दर्ज हुआ था।

कानपुर से शुरू हुआ विवाद

कानपुर पुलिस ने चार सितंबर को बारावफात के जुलूस के दौरान एक सार्व. जनिक सड़क पर आई तब मोहम्मद लिखे बोर्ड के आरोप में नौ नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद यह विवाद शुरू हो गया।

मुझे गोली मार दो, मोहम्मद के नाम मरना कबूल : तौकीर

मौलाना तौकीर रजा खां ने शुक्रवार की रात 10:20 बजे वीडियो जारी किया। कहा कि अतीक और अशरफ की तरह मुझे गोली मार दो, मोहम्मद के नाम पर मरना कबूल है। उन्होंने कहा कि वह अभी तक नजरबंद हैं। वहीं, मुसालमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने घटना को सोची–समझी साजिश बताया।

ऐसी कार्रवाई करें कि दोबारा गलती की न सोच सकें उपद्रवी : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो उपद्रवी दोबारा गलती करने के बारे में सोच भी व सके।

.प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

पीएसयू की खबरें

ऑयल इंडिया ने अंडमान के उथले अपतटीय खंड में प्राकृतिक गैस की खोज की

नई दिल्ली। ऑयल इंडिया लि. (ओआ. ईएल) ने अंडमान द्वीप समूह के पास प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने खोज के आकार के बारे में जानकारी नहीं दी। एक बयान में, ओआईएल ने कहा कि अपतटीय अंडमान ब्लॉक एएन–ओएसए. चपी–2018६1 में खोदे गए दूसरे अन्वेषण कुएं विजयपुरम–2 में प्राकृतिक गैस की उपस्थिति की सूचना मिली है। बयान में कहा गया कि शुरुआती जांच के दौरान, जब कुएं से गैस रुक–रुक कर बाहर निकल रही थी, तो उसके नमूनों की जांच की गई। इस जांच से यह पुष्टि हो गई है कि वहां प्राकृतिक गैस मौजूद है। यह गैस कैसे और कहां से आई है, यह जानने के लिए आगे और गैस आइसोटोप अध्ययन किए जा रहे हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अंडमान सागर में हाइड्रोकार्बन भंडारों की खोज कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस खोज से भारत की तेल और गैस की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। ओआईएल ने कहा कि शुरुआती आकलन के अनुसार, हमारी यह खोज हाइड्रोकार्बन के स्रोत, उसके प्रवाह मार्ग या उसके जमाव की उपस्थिति का एक प्रमुख संकेत हो सकती है, जो भविष्य की खोज और ड्रिलिंग रणनीति में मदद करेगी। ओआईएल गैस की उपस्थि. ति का मूल्यांकन करने के लिए ऊपरी संभावित क्षेत्रों में भी अतिरिक्त परीक्षण कर रही है। कंपनी ने आगे कहा कि अंडमान के उथले अपतटीय क्षेत्र में जारी खोज अभियान के दौरान हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति की सूचना मिलने का यह पहला मामला है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया कि यह खोज अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से 9.20 समुद्री मील (17 किलोमीटर) दूर, पानी की 295 मीटर गहराई पर और कुल 2,650 मीटर की लक्ष्यित गहराई वाले कुएं में हुई है। पुरी लंबे समय से अंडमान को गुयाना स्तर का तेल क्षेत्र बताते रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2,212 से 2,250 मीटर की गहराई में कुएं के शुरुआती उत्पादन परीक्षण से पता चला कि वहां प्राकृतिक गैस है। पानी के जहाज से काकीनाड़ा लाए गए गैस के नमूनों की जांच की गई, जिसमें 87 प्रतिशत मेथेन पाया गया।

एसजेवीएन ने 10,647 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन हासिल किया

एसजेवीएन की 37वीं वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने दी जानकारी

शिमला। एसजेवीएन लिमिटेड, एक अग्रणी नवरत्न सीपीएसई, ने अपनी 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ताने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 में कंपनी की प्रचालन, वित्तीय एवं रणनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित किया। गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024–25 प्रचालन उत्कृष्टता का एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। एसजेवीएन ने अपनी सभी प्रचालनरत परियोजनाओं से 10,647 मिलियन यूनिट का अब तक का सर्वोच्च विद्युत उत्पादन हासिल किय. ा। 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जल.

विद्युत स्टेशन ने 3450.98 मिलियन यूनिट का अब तक का सर्वोच्च तिमाही विद्युत उत्पादन, 39.572 मिलियन यूनिट का सर्वोच्च एकल–दिवसीय विद्युत उत्पादन और 1222.170 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड मासिक उत्पादन किया। इसी प्रकार, 412 मेगावाट रामपुर जलविद्युत स्टेशन ने 292.331 मिलियन यूनिट का अपना अब तक का सर्वोच्च मासिक विद्युत उत्पादन और 11.023 मिलियन यूनिट के सर्वोच्च एकल–दिवसीय विद्युत उत्पादन के साथ 955.616 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड तिमाही विद्युत उत्पादन दर्ज किया। 60 मेगावाट नैटवाड़ मोरी जलविद्युत स्टेशन ने अपनी डिजाइन एनर्जी को पार करते हुए अपने प्रथम प्रचालन वर्ष में 316.40 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन हासिल किया। गुप्ता ने बताया कि एसजेवीएन ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में सुदृढ़ वित्तीय परिणाम दर्ज किए हैं। प्रचालन से राजस्व बढ़कर 2,897.25 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के 2,533.59 करोड़ रुपए से 363.66 करोड़ रुपये अधिक है। स्टेंडएलोन कर–पश्चात लाभ (पीएटी) भी बढ़कर 970.18 करोड़ रुपए हो गया, जो गत वर्ष के 908.40 करोड़ रुपए से 61.78 करोड़ रुपए अधिक है। कंपनी के बोर्ड ने 0.31 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अंतरिम लाभांश सहित कुल लाभांश 1.46 रुपए प्रति शेयर हो जाएगा। कंपनी ने इस क्षेत्र में सबसे स्वस्थ प्राप्य अनुपातों में से एक को बनाए रखते हुए सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन को प्रदर्शित करते हुए 15 दिनों के राजस्व का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ट्रेड प्राप्य स्तर हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिनांक 30 अगस्त 2024 को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। यह उपलब्धि भारत के विद्युत क्षेत्र परिवर्तन में एसजेवीएन की प्रचालन उत्कृष्टता, वित्तीय सुदृढ़ता और रणनीतिक महत्व को प्रदर्शित करती है। अप्रैल 2024 से, पोर्टफोलियो में 12 परियोजनाओं से 691 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है, जिससे कुल स्थापित क्षमता 2967.52 मेगावाट हो गई है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट की प्रथम इकाई को दिनांक 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज किया गया और प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन दिनांक 22 अगस्त 2025 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, एसजेवीएन ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका सृजन और सामुदायिक अवसंरचना विकास आदि जैसे शीर्षों के अंतर्गत पहलों के साथ कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर ₹31.24 करोड़ का व्यय किया है। डीपीई के तहत 'उत्कृष्ट' कारपोरेट अभिशासन रेटिंग को बनाए रखते हुए, कंपनी कार्बन उत्सर्जन में कटौती और भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए अपनी परियोजनाओं को निरंतर आगे बढ़ा रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु, एसजेवीएन के लिए 13090 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन और 12,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स का एमओयू लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान, कंपनी ने 3681.60 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन, 822.4 करोड़ रुपए का राजस्व और 258.51 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है। गुप्ता ने अपने संबोधन के समापन पर भारत सरकार, राज्य सरकारों, प्रमुख मंत्रालयों और भागीदार संस्थानों के प्रति

एसजेवीएन कारपोरेट मुख्यालय में हिन्दी पखवाड़े का उदघाटन कार्यक्रम

उनके निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी हितधारकों का भी आभार व्यक्त किया और बोर्ड तथा एसजेवीएन कर्मचारियों के समर्पण को कंपनी का वास्तविक सामर्थ्य बताया। उत्कृष्टता और स्थायी विकास के प्रति एसजेवीएन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, उन्होंने विकसित और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में इसकी भूमिका पर बल दिया।

शिमला। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेन्द्र गुप्ता के मार्गदर्शन में कारपोरेट मुख्यालय, शिमला में हिन्दी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में अजय कुमार शर्मा, निदेशक (कार्मिक), एसजेवीएन मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी पखवाड़े की बधाई दी और हिन्दी पखवाड़े की महता पर प्रकाश डाला।

निदेशक (कार्मिक) ने सभी कर्मचारिया. ें से पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में बढ़–चढ़ कर भाग लेने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने राजभाषा हिन्दी के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि भाषा विचार अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम है। विविधता से सम्प. न्न भारत में हिन्दी भाषा विभिन्न संस्कृ तियों, समुदायों, संप्रदायों को जोड़ने का कार्य करती है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं। यह हमारी संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है। दुनिया में हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम ऐसी भाषा से जुड़े हैं, जो वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान कायम कर रही है। हिन्दी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 28 सितंबर, 2025 तक किया जाएगा, जिसमें एसजेवीएन कारपोरेट मुख्यालय सहित परियोजना कार्यालयों में अधिका. रियों एवं कर्मचारियों के मध्य हिन्दी को बढ़ावा देने एवं उनके मध्य हिन्दी के प्रति स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक की भावना को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न प्रतियो. गिताओं का आयोजन किया जा रहा है। कारपोरेट मुख्यालय में हिन्दी पखवाड़े के दौरान निगम मुख्यालय में शुद्ध शब्द लेखन, श्रुतलेखन, काव्य–गोष्ठी तथा सुलेख आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक (मा सं), श्री चंद्रशेखर यादव सहित कारपोरेट मुख्यालय के विभिन्न विभागोंध्अनुभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित शुद्ध शब्द लेखन प्रतियोगिता में 60 अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया।

एसजेवीएन लिमिटेड के 'नराकास प्रोत्सा. हन सम्मान''' 2024–25 के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित

शिमला। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भूपेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समि. ति, शिमला (कार्यालय–2) को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नराकास प्रोत्साहन सम्मान दृ2024–25 के उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हिंदी दिवस–2025 और पां. चवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर प्रदान किया गया। इस अवसर पर भूपेन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने कहा कि यह सम्मान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समि. ति, शिमला (कार्यालय–2) के सदस्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्य–. निष्पादन के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर राजभाषा काया. र्न्वयन समिति, शिमला (कार्यालय–2) आगे भी अपने सदस्य कार्यालयों में रा. जभाषा में और अधिक प्रयोग के लिए सभी के साथ मिलजुल कर प्रयास करती रहेगी। इस अवसर पर अजय कुमार शर्मा, निदेशक(कार्मिक), एसजेवीएन ने बताया कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग एवं प्रसार की सराहना के लिए इस सम्मान की स्थापना संपूर्ण भारत में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए की गई है। इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत में गठित नराकास द्वारा प्राप्त प्रविष्टिया. ें का मूल्यांकन कर राजभाषा नीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया गया है। यह पुरस्कार श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के कर कमलों से आशीष पंत, महाप्र. बंधक(राजभाषा), एसजेवीएन–सह–सद. स्य–सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिमला (कार्यालय–2) ने गांधी नगर, गुजरात में आयोजित एक समा. रोह के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्य कार्य–निष्पादन हेतु प्राप्त किया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक आधिकारिक समिति है, जो भारत सर. कार के विभिन्न कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी और प्रोत्साहन हेतु गठित की जाती है। यह समिति विशेष रूप से नगर या क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करती है, जिसकी अध्यक्षता उस नगर के वरिष्ठतम केंद्र सरकार के अधिकारी करते हैं। शिमला स्थित नराकास(कार्यालय–2) के अध्यक्ष एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

.प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए आरईसी की ₹5.71 करोड़ की मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को हरी झंडी

अलवर,राजस्थान। दूरस्थ समुदायों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के अपने मिशन के अनुरूप, आरईसी लिमिटेड ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, अलवर को तीन वर्षों की अवधि में पाँच मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) के संचालन के लिए ₹5.71 करोड़ का सहयोग दिया है।इन एमएमयू को 5 अक्टूबर, 2025 को माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा विज्ञान एवं प्रौद्यो. गिकी मंत्री, राजस्थान सरकार श्री संजय शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस समारोह में आरईसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) टीम और महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष एम. एल. मीणा के साथ–साथ जिला प्रशासन और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।जीपीएस–सक्षम ट्रैकिंग सिस्टम से लैस, ये एमएमयू राजस्थान के कुछ सबसे वंचित और आ. दिवासी इलाकों को कवर करते हुए, अलवर, भरतरी और बहरोड़–को. टपुली जिलों के समुदायों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाएँगे। इस पहल से हर महीने 10,000 से ज़्यादा लोगों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श, उपचार, दवाइयाँ और निवारक स्वास्थ्य सेवा जागरूकता का लाभ मिलने की उम्मीद है।

टी एस सी बोश को आरईसी के निदेशक (परियोजनाएँ) का कार्यभार

नई दिल्ली। टी एस सी बोश ने 3 अक्टूबर 2025 को आरईसी लिमिटेड के निदेशक (परियोजनाएँ) का कार्यभार संभाला है। 1 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी के बाद, विद्युत मंत्रालय ने आज इस संबंध में एक आदेश जारी किया। विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक के व्यापक अनुभव के साथ, श्री बोश ने कई प्रमुख नेतृत्व पदों पर कार्य किया है, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना भी शामिल है। उन्होंने रणनीतिक निर्णय लेने, व्यवसाय विकास और सभी हितधारकों के साथ समन्वय में भी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है।

उन्होंने भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत प्रमुख राष्ट्रीय विद्युतीकरण पहलों के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उल्लेखनीय रूप से, उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिससे हजारों दूरदराज के गाँवों में बिजली पहुँची, और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य योजना, जिसके माध्यम से देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त हुआ, के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आरईसी में कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग) के रूप में अपनी पिछली भूमिका में, उन्होंने राज्य के स्वामित्व वाली और निजी क्षेत्र की संस्थाओं, दोनों में बिजली और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण में असाधारण परियोजना नेतृत्व और रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मूल्यांकन और वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत सरकार की बड़े पैमाने पर बिजली पारेषण और वितरण परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन किया है।

विविध व्यावसायिक क्षेत्रों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता और उनकी मजबूत विश्लेषणात्मक और प्रबंधकीय कुशाग्रता ने भा.

रत के बिजली क्षेत्र में एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में आरईसी के निरंतर विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी रणनीतिक निगरानी व्यावसायिक विकास, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, परियोजना निगरानी और कॉर्पोरेट संचार सहित कॉर्पोरेट कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला तक फैली हुई है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व और गहन क्षेत्रीय विशेषज्ञता देश के विद्युत और अवसंरचना विकास में एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में आरईसी की भूमिका को आकार दे रही है।

आरईसीपीडीसीएल ने अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना की एसपीवी, एसआर डब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को मेसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सौंपा

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), जो विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में महारत्न सीपीएसयू, आरईसी लि. मिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने टीबीसीबी रूट के तहत आईएसटीएस ट्रांसमिशन परियोजना के लिए एक परियोजना विशिष्ट एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) अर्थात एसआर डब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 17 अक्टूबर 2025 को मेसर्स पावर ग्रिड कॉर्पो. रेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया।

मेसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर ट्रांसमिशन परियोजना के विकास के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक आरईसीपीडीसीएल द्वारा आयोजित टैरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोलीदाता के रूप में उभरी।

आरईसीपीडीसीएल ने अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना के एसपीवी, अनंतपुरम II पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को मेसर्स शिवालय कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को सौंप दिया

आरईसीपीडीसीएल के सीईओ सौरभ रस्तोगी ने आरईसीपीडीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कंपनी सचिव सत्यप्रकाश दाश को एसपीवी सौंपा। परियोजना की कार्यान्वयन अवधि 24 महीने है। इस योजना में परली न्यू (महाराष्ट्र) – बीदर (कर्नाटक) लगभग 109 किलोमीटर लंबी 765 केवी डबल सर्किट लाइन की स्थापना शामिल है।

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), जो विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में महारत्न सीप. ीएसयू, आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने टीबीसीबी रूट के तहत आईएसटीएस ट्रांसमिशन परियोजना के एक प. रियोजना विशिष्ट एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) अर्थात अनंतपुरम प्प पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 17 अक्टूबर 2025 को मेसर्स शिवालय कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को सौंप दिया।

मेसर्स शिवालय कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर ट्रांसमिशन परियोजना के विकास के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक आरईसीपीडीसीएल द्वारा आयो. जित टैरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोलीदाता के रूप में उभरी।

आरईसीसीएल के सीईओ श्री सौरभ रस्तोगी ने आरसीपीसीएल, शिवालया अमीट्रिक लिमिटेड और सेंट्रल ग्रेटर यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति शिवालया अमीट्रिक लिमिटेड के प्रमुख (विद्युत एवं परिवहन) राजेश कुमार सिंह को दी। परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि 30 माह है। इस योजना में मोटे तौर पर 765ध्400 केवी सीएनशहल्ली स्टेशन (कर्नाटक) की स्थापना, अनंतपुरम–प्प पीएस से सीएनशहल्ली तक लगभग 181 किलोमीटर की 765 केवी डबल सर्किट लाइन और अनंतपुरम–प्प पूलिंग स्टेशन (आंध्र प्रदेश) का विस्तार, तथा अन्य संबंधित कार्य शामिल हैं।**प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क**

प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कांस्टीट्यूशन क्लब में बीएसपीएस का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित

मीडिया पार्टनर, प्राइम इंडिया मीडिया हाउस ने दमदार भूमिका निभाई

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में मोदी विजन, पावरफुल इंडिया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (बीएसपीएस) ने किया और इस सेमिनार में मीडिया पार्टनर प्राइम इंडिया मीडिया हाउस ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ला थे और इसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद जगदंबिका पाल ने की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने द्वीप प्रज्वलन कर शुरुआत की। इस यादग. ार मौके पर बीएसपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नासिर खान,बीएसपीएस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा देश भर से आए संगठन के प्रमुख लोग,पत्रकार व विभिन्न क्षेत्रों की जानी–मानी हस्तियां उपस्थित थीं। सेमिनार में शिरकत करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आयोजन स्थल में बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गई। 16 सितंबर की शाम 3–6 बजे तक आयोजित किए गए इस सेमिनार में महिला पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।बीएसपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद जगदंबिका पाल ने अध्यक्षता की

संजय सिंह ने आगंतुकों का अपने वेलकम स्पीच से इस्तकबाल किया। श्री सिंह ने महामहिम राज्यपाल श्री शुक्ला के गोरखपुर की राजनीति की शुरुआती दिनों की यादें ताजा कर कहा कि महामहिम जब विधायक थे तो भी उनके खिलाफ भी आलोचनात्मक खबरें किया करते थे लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत कभी नहीं की। कार्यक्रम के अध्यक्ष व सांसद जगदंबिका पाल का भी श्री सिंह ने हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि सांसद जी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सांसद जी इस तरह से जन सेवा करते हैं कि साथ वाले को पता भी नहीं लगता। इन्हें खुशी तभी मिलती है जब तक कुछ लोगों को रोज भोजन नहीं करा लेते। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिंह ने कार्यक्रम के मोदी विजन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता की वजह से आज भारत, पावरफुल इंडिया बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। अपने अध्यक्षीय भाषण में सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से आज अमेरिका जैसा देश फिर इंडिया की तरफ देख रहा है लेकिन प्रधानमंत्री ने चीन दौरे में स्वदेशी ताकत को बताकर साबित कर दिया है कि भारत किसी का मोहताज नहीं है। अर्थात भारत की स्वदेशी ताकत भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाने के मंत्र की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मौके पर दैनिक भास्कर के समाचार संपादक मुकेश कौशिक ने मोदी विजन और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोलते हुए कहा कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हमारा देश अग्रसर है और यह सब मोदी विजन का कमाल है। देशभर से आए पत्रकार और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को सुनना चाहते थे, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने बोलने के लिए आमंत्रित किय. ा।मुख्य अतिथि हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि वह संवैधानिक पद पर है और दलीय राजनीति से परे हैं इसलिए उनका दायित्व है कि कोई राजनी. तिक वक्तव्य ना दे। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने आज विश्व के धुरंधर को भारत के सामने नतमस्तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब अरुण जेटली भारत के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने उस दौरान वित्त राज्य मंत्री के तौर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जिसे लेकर खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली असमंजस में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत को आत्मसात कर भ. ारत को हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। उन्होंने प्रधानमंत्री के 56 इंच की छाती की तारीफ करते हुए कहा कि आज भारत स्वदेशी के मूल मंत्र से आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने इसकी कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शूलपानी सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता वी राज बाबुल, राष्ट्रीय सचिव स्नेहलता,भानु सिंह , आशुतोष मणि त्रिपाठी, राजस्थान के एमपी शर्मा,पश्चिम बंगाल के नीरज बारसोई, झारखंड रांची के संतोष पाठक, यूपी के सोनभद्र से विवेक पांडे, दार्जिलिंग के पवन शुक्ला समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।

.प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 40 से अधिक लोगों की मौत

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ मचने से 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी. सेंथिल कुमार ने मीडिया को बताया है कि हादसे में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 95 घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे पर तमिलनाडु के सीएम एम।के। स्टालिन की ओर से जारी बयान में मृतकों के परिवारों को 10–10 लाख रुपये के मुआवजे का एलान भी किया गया है।वहीं एक्टर विजय ने सोशल मी. डिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करके इस घटना के लिए बेहद दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह गहरी पीड़ा में हैं।ये हादसा उस वक्त हुआ जब शनिवार शाम विजय करूर में तमिलगा वेट्री कड़गम पार्टी की एक रैली को संबोधित कर रहे थे।

विजय ने घटना पर जताया दुख

रैली में मची भगदड़ के बाद विजय ने एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है। उन्होंने लिखा, 'मेरा दिल टूट गया है। मैं असहनीय दर्द और दुख में हूं, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। करूर में जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा?

हादसे के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने जिले में इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू करने के लिए कहा है। हालांकि, कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि ने सोशल मीडिया पर लिखा कि करूर में हुई राजनीतिक रैली में बच्चों समेत निर्दोष लोगों की मौत बेहद दुखद और पीड़ादायक है। इस दुखद घड़ी में मैं अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं और घायल हुए लोगों के जल्द ठीक

होने की प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव मदद करें और पीड़ितों के जल्द इलाज के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक्स पर इस घटना के बारे में लिखा कि मैंने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री एम। सुब्रमण्यम और जिलाधिकारी से संपर्क किया है ताकि भीड़ की वजह से बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हुए लोगों को तुरंत इलाज मिल सके।उन्होंने यह भी कहा कि वह जनता से डॉक्टरों और पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं।

हादसा कैसे हुआ?

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता सेंथिल बालाजी शनिवार रात करूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से कहा कि घटना के बाद सीएम ने तुरंत पूछ. ताछ की और जिला कलेक्टर, एसपी और उन्हें अस्पताल पहुंचने का आदेश दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने पत्रकारों से कहा कि करूर में विजय की रैली में भगदड़ में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है और उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश पर त्रिची से एक मेडिकल टीम करूर जा रही है। मैं भी आज रात करूर जा रहा हूं। तमिलनाडु के विपक्ष के नेता और एआईएडीएमके महासचिव के पलानीस्वामी ने एक्स पर लिखा कि करूर में तमिलगा वेट्री कड़गम पार्टी की चुनावी रैली में, जहां उसके नेता विजय ने भाषण दिया, भीड़ की अफरा–तफरी के दौरान कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेहोश होकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं।ष्उन्होंने लिखा, यह खबर दुखद है। मैं अपनी गहरी संवेदनाएं और दुख उन परिवारों के प्रति व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिजन खो दिए। जब विजय सभा को संबोधित कर रहे थे, तब भीड़ बढ़ती गई और बेकाबू हो गई। इस दौरान कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद विजय ने अपना भाषण रोककर, खास तौर पर बनाई गई प्रचार बस के ऊपर से लोगों के लिए पानी की बोतलें फेंकीं। भारी भीड़ के कारण एंबुलेंस को भी घटनास्थल तक पहुंचने में परेशानी हुई।

घटना के जांच के लिए बना एसआईटी

मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच से इनकार करते हुए तमिलनाडु सरकार और राजनीतिक दलों को सख्त एसओपी बनाने का सुझाव दिया है। अदालत ने साफ किया कि राजनीतिक रैलियों और बैठकों के आयोजन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घटना की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (उत्तर) असरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

एक्टर विजय की पार्टी ने रखा अपना पक्ष

तमिलगा वेत्री कझगम ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए भगदड़ की जिम्मेदा. री पुलिस पर डाली। पार्टी का कहना था कि जब समर्थक विजय से मिलने का इंतजार कर रहे थे, तभी भीड़ में कुछ लोगों ने चप्पलें फेंकीं। इसके बाद पुलिस ने बिना चेतावनी दिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। टीवीके ने आरोप लगाया कि पुलिस हालात को संभालने में नाकाम रही। टीवीके के वकील का कहना था कि पुलिस ने भीड़ को संभालने में गंभीर लापरवाही की और अगर स्थिति को शांत तरीके से संभ. ाला जाता तो भगदड़ नहीं होती। वहीं, तमिलनाडु पुलिस ने पलटवार करते हुए टीवीके पर आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने समर्थकों की सुरक्षा को लेकर खुद लापरवाही बरती।

.प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

केरल में कई लोगों को 'ब्रेन ईटिंग अमीबा' बीमारी से हुई मौत, क्या है यह बीमारी

केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा का मामला फिर से एक बार चर्चा में है। कई मी. डिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में सि. तंबर के मध्य तक इसके 60 से अधिक मामले पाए गए हैं जिनमें कम से कम 18 लोगों की मौतें हुई हैं। राज्य के विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने केरल सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस बीमारी के इतने बड़े पैमाने पर फैलने के बारे में कोई ठोस वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने में नाकाम रही है। विधानसभा में आईयूएमएल के नेता एन शम्सुद्दीन ने दावा किया कि यह बीमारी तेजी से फैल रही है और इसके मामले तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, मलप्पुरम, त्रिशूर और पालक्कड़ समेत कई जिलों में पाए गए हैं। हालांकि केरल सरकार का कहना है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है।

लगातार बढ़ते मामलों पर राजनीतिक बयानबाजी

लेफ्ट विधायक टीआई मधुसूदानन ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पिनराई विजयन की सरक. ार सार्वजनिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक महत्व देती है।साथ ही वर्तमान हालात को देखते हुए केरल के स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में इस बीमारी को लेकर विशेष दिशानिर्देश जारी किए थे। केरल में साल 2023 से ब्रेन ईटिंग अमीबा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इन मामलों पर काबू पाने में नाकामी के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। स्वास्थ्य मंत्री ने लेफ्ट सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि उसने संक्रमण पर काबू पाने के उपाय किए हैं। साथ ही उन्होंने पिछली यूडीएफ सरकार पर आरोप लगाया कि वह संक्रमण से जुड़ी शोध रिपोर्ट पर बैठी रही और उसको लेकर कोई काम नहीं किया। लेकिन शोध रिपोर्ट साल 2018 में प्रकाशित हुई थी जब सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार थी और केके शैलजा स्वास्थ्य मंत्री थीं। इसको लेकर वीना जॉर्ज की आलोचनाएं भी हुई हैं।

आखिर यह बीमारी क्या है?

असल में इस बीमारी को प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोइन्सेफ्लाइटिस (पीएएम) के नाम से जाना जाता है, जो कि नीग्ले. रिया फॉवलेरी अमीबा की वजह से होती है। असल में यह एक प्रकार का दुर्लभ दिमागी संक्रमण है। अधिकतर मामलों में स्वीमिंग पूल या तालाब में तैरने के दौरान एन। फॉवलेरी अमीबा इंसानी शरीर में नाक के माध्यम से पहुंचता है और यहां से वो ब्रेन के नीचे मौजूद क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से होते हुए दिमाग में पहुंचता है। पत्रकार इमरान कुरैशी ने जुलाई 2024 में इस बीमारी से जिंदा बचे एक 14 वर्षीय किशोर पर रिपोर्ट की थी। इस दौरान उनसे खास बातचीत में कोझिकोड में बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स इन्टेंसिविस्ट डॉ. अब्दुल रऊफ ने बताया था कि यह एक पैरासाइट (परजीवी) है जो अलग–अलग केमिकल छोड़ता है और दिमाग को नष्ट करता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं– बुखार, तेज सिरदर्द, गले में खराश होना, अचेत होना, दौरा पड़ना और कोमा के हालात। सिर में अत्यधिक दबाव के कारण कई

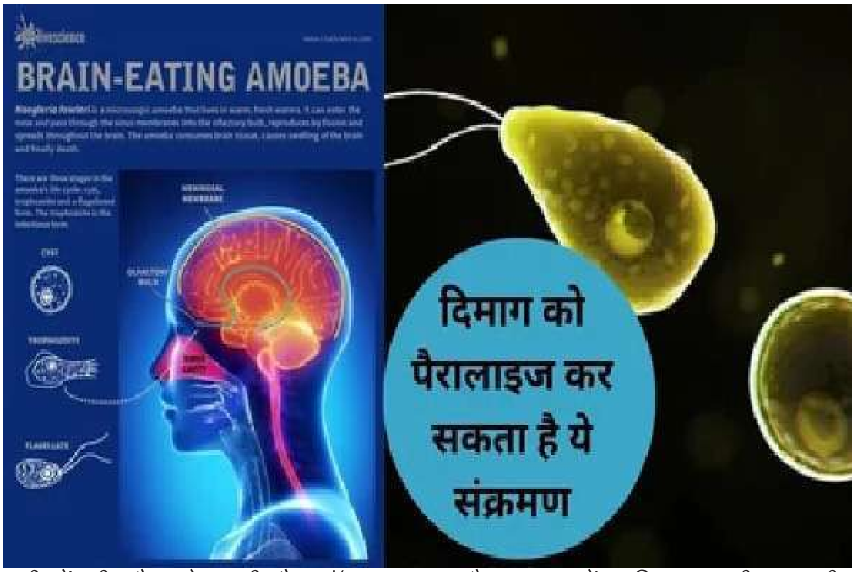

मरीजों की मौत हो जाती है। डॉ. रऊफ ने कहा कि यह ताजे पानी वाली झीलों में पाया जाता है, खासकर गर्म पानी वाली झीलों में। यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को पानी में कूदना या फिर इसमें डुबकी लगानी नहीं चाहिए। इसी के जरिए अमीबा शरीर में प्रवेश करता है। अगर पानी प्रदूषित है, अमीबा आपकी नाक के रास्ते शरीर में दाखिल होता है। सबसे अच्छा है कि प्रदूषित जलाशयों और यहां तक कि स्वीमिंग पूल से दूर रहा जाए या फिर तैराकों को अपना मुंह पानी से ऊपर रखना चाहिए। पानी में क्लोरीन डालना बेहद जरूरी है। लेकिन कर्नाटक के मंगलूरु में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी एक रिसर्च पेपर में नवजातों में एन. फॉवलेरी अमीबा संक्रमण के मामलों का हवाला भी दिया गया है, जो पानी के स्रोतों से हुए। यहां नहाने वाला पानी भी इस बीमारी का स्रोत था। इस बीमारी में मृत्यु दर लगभग 97 फीसदी है। अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से छपे एक रिसर्च पेपर के मुताबिक, साल 1971 और 2023 के बीच इस जानलेवा बीमारी से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको और पाकिस्तान जैसे चार देशों में पीड़ित हुए कुल लोगों में से सिर्फ आठ लोग ही बच पाए। यह भी तब संभव हुआ जब बीमारी के बारे में 9 घंटे से पांच दिन के अंदर ही पता चल गया था। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अमेरिका में अप्रैल 2024 में पाकिस्तान की एक टीम द्वारा प्रकाशित रिसर्च पेपर के अनुसार, इस बीमारी से बचने वालों की उम्र नौ साल से 25 साल के बीच है।

क्या है इलाज?

डॉक्टरों का मानना है कि शुरुआत में ही अगर इस मर्ज का पता लग जाए तो मरीज के इलाज में बहुत आसानी हो सकती है और उसे बचाया जा सकता है। इस बीमारी में आमतौर पर डॉक्टर लक्षण शुरू होने के 24 घंटे के अंदर लंबार ट्रीटमेंट और एंटी माइक्रोबियल दवाओं के कॉम्बिनेशन (अम्फोटेरिसिन बी, रिफाम्पिन और एजिथ्रोमाइसिन) का इस्तेमाल करते हैं। डॉ. रऊफ बताते हैं कि मरीज के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (सीएसएएफ) में एन. फॉवलेरी का पता लगाने के लिए पीसीआर (पोलीमरेज चेन रिएक्शन) टेस्ट किया जाता है। वो कहते हैं कि मरीज को मिल्टेफोसिन दवा दी जा सकती है, जो कि पहले मिलना मुश्किल होती थी। जब ऐसे मामले सामने आने लगे तो सरकार ने इसे जर्मनी से आयात किया। इस दवा का इस्तेमाल भारत में दुर्लभ बीमारियों के इलाज में किया जाता है लेकिन यह बहुत महंगी नहीं है। मरीज के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी कई मामलों में अगले एक महीने तक उसकी दवा चलती है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि इस बीमारी का सबसे बेहतर इलाज परहेज है, दूषित पानी वाले तालाब, कुओं और स्वीमिंग पूल में न नहाया जाए।

तालाबों और झीलों में पाया जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा

ब्रेन ईटिंग अमीबा, वैज्ञानिक रूप से नेग्लरिया फाउलेरी कहा जाता है, एक सूक्ष्मजीव है जो गर्म, ताजे, रुके हुए पानी जैसे तालाबों और झीलों में पाया जाता है। यह नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, दिमाग तक पहुंचता है और ब्रेन टिश्यूज को नष्ट कर देता है, जिससे प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस नामक एक जानलेवा संक्रमण होता है। शुरुआती लक्षणों में सिरदर्द, बुखार, उल्टी और गर्दन में अकड़न शामिल हैं, जिसके बाद मानसिक भ्रम, दौरे, और कोमा हो सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए अशुद्ध पानी से दूर रहना और नाक में पानी जाने से रोकना महत्वपूर्ण है, जैसे कि तैरते समय या नाक पर क्लिप लगाकर रखें।

लक्षण

यह संक्रमण एक दुर्बल करने वाला मस्तिष्क संक्रमण है और इसके लक्षण कई अन्य सामान्य बीमारियों से मिलते–जुलते हैं, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। तेज सिरदर्द, बुखार, मतली और उल्टी, गर्दन में अकड़न, मानसिक भ्रम, दौरे और कोमा।

बचाव के तरीके

तालाबों, झीलों और रुके हुए पानी में तैरने से बचें, खासकर गर्म पानी में। तैरते या नहाते समय नाक में पानी जाने से रोकने के लिए नाक क्लिप का उपयोग करें या अपनी नाक को ऊपर रखें। स्विमिंग पूल और अन्य सार्वजनिक जल निकायों में क्लोरिनेटेड और साफ पानी का ही उपयोग करें।

इलाज

समय पर निदान और इलाज जीवन बचा सकता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से अमीबा की पहचान की जा सकती है। मिल्टेफोसिन जैसी कुछ दवाएं संक्रमण के बाद प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन समय पर इलाज मिलना महत्वपूर्ण है।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

राजस्थान:बैल खरीदने गए आसिफ को गो-तस्करी के शक में पीटा, बाद में मौत

राजस्थान के भीलवाड़ा में गो–तस्करी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने 32 साल के आसिफ पर हमला कर दिया था. चार दिन बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई. यह घटना 15 और 16 सितंबर की दरमियानी रात को हुई. आसिफ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मुल्तानपुरा गांव के निवासी थे.

फोन पर बातचीत में आसिफ के ममेरे भाई मंजूर पेमला ने बताया, मेरे भाई को गो–तस्करी के शक की वजह से लगभग 14–15 लोगों ने पहले तो खूब मारा, उसके पैसे छीन लिए. फिर वही लोग कह रहे हैं कि गलती मेरे भाई की है. मेरा भाई सिर्फ पशु खरीदने गया था.

भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में अब तक पाँच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने क्या-क्या बताया?

भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है. उन्होंने कहा, हमें खबरियों के नेटवर्क से इस घटना की सूचना मिली थी. त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक पाँच लोगों की गिरफ्तारी की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है, जो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.

आसिफ की मौत के बाद उनके पीछे पत्नी, आठ महीने का बेटा और ढाई साल की बेटी रह गए हैं.

परिवार की तरफ से बीबीसी को साझा की गई अस्पताल में भर्ती आसिफ की तस्वीरों में उनके पूरे बदन पर गहरे जख्म दिखाई दे रहे हैं. तस्वीरों में उनका शरीर लाल और काले निशानों से भरा हुआ है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आसिफ की मौत किस कारण हुई, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है. मेडिकल बोर्ड की तरफ से विस्तृत जांच की जा रही है. हालांकि आसिफ के परिजनों का आरोप है कि उनकी मौत मॉब लिंचिंग के कारण हुई है.

मंजूर पेमला का कहना है, मेरा भाई मुसलमान था. इसलिए उसके पास गाय–बैल होना पाप था. वो खेती के लिए पशु खरीदने गया था. उसकी जगह कोई हिन्दू भाई होता तो ये घटना नहीं होती.

परिजनों ने क्या बताया?

मंजूर की ओर से दर्ज कराई गई एफआ. ईआर की कॉपी बीबीसी हिंदी ने देखी है. एफआईआर के अनुसार, आसिफ अपने साथी मोहसिन के साथ 16 सितंबर को मंदसौर से राजस्थान के भीलवाड़ा आए थे. वे लाम्बिया रायला पशु मेले से बैल खरीदकर लौट रहे

हमने मेले से बैल ख़रीदे और पिकअप में रखकर मंदसौर की ओर चल दिए. रास्ते में रुककर खाना भी खाया. लेकिन वहां से चलने के बाद हमें लगा कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं. थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने हमारी पिकअप को सड़क किनारे धकेल दिया.

मोहसिन
पीड़ित

“

हमें ख़बरियों के नेटवर्क से इस घटना की सूचना मिली थी. त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक पाँच लोगों की गिरफ़्तारी की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है, जो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.

धर्मेंद्र सिंह

पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा

थे. इसी दौरान उन पर भीड़ ने हमला कर दिया.

हमले में आसिफ के साथ मौजूद मोहसिन को भी भीड़ ने पीटा, लेकिन वे जान बचाकर भागने में सफल रहे.

मोहसिन ने बताया, हमने मेले से बैल खरीदे और पिकअप में रखकर मंदसौर की ओर चल दिए. रास्ते में रुककर खाना भी खाया. लेकिन वहां से चलने के बाद हमें लगा कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं. थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने हमारी पिकअप को सड़क किनारे धकेल दिया.

मोहसिन के मुताबिक, मजबूरन हमें गाड़ी रोकनी पड़ी और तभी दर्जनभर से ज़्यादा लोगों ने हमें गाड़ी से नीचे खींचकर बेरहमी से मारना शुरू कर दिया. वे लोग बार–बार हमें गो तस्कर कहकर पीट रहे थे और उन्होंने जानवरों की खरीद की रसीद भी छीन ली.

मोहसिन ने आगे कहा, मारपीट के बीच ही मैं किसी तरह सड़क किनारे जंगल की तरफ भागा. मैं लगातार दौड़ता रहा और पूरी रात डर से वहीं जंगल में छिपा रहा. रोते हुए मोहसिन ने कहा, मेरा भाई भीड़ के हाथ चढ़ गया. वो लोग रुकने को तैयार नहीं थे और आसिफ को लगातार मार रहे थे. आ. सिफ चिल्लाता रहा और मैं जंगल की ओर भागता रहा.

मारने वाले कई लोग पहचान के हैं

मोहसिन ने बताया कि मारने वालों में कई ऐसे लोग थे जिन्हें वह पहचानते हैं. उन्होंने कहा, उनमें से कुछ लोगों का तो धंधा ही यही है. इन्होंने पहले भी गांव के कई मुस्लिम लड़कों के साथ ऐसे ही गो–तस्करी का आरोप लगाकर मारपीट की है.परिवार का आरोप है कि आसिफ पर हमले के बाद भी उत्पीड़न रुका नहीं.

एफआईआर में मंजूर पेमला के हवाले से लिखा है, रात करीब साढ़े तीन बजे मेरे पास फोन आया. उस तरफ से किसी ने कहा कि हमने आसिफ को पकड़ रखा है. उससे 36 हजार रुपये हम ले चुके हैं. अगर तुम चाहते हो कि वह जिंदा बचे तो 50 हजार रुपये और लेकर आओ, वरना हम उसे मार देंगे.

मंजूर ने यह भी बताया कि अगले दिन सुबह उन्हें इंस्टाग्राम पर इस घटना से जुड़े वीडियो और पोस्ट दिखे थे. इस बीच परिवार मोहसिन से संपर्क करने और जानक. ारी जुटाने की कोशिश करता रहा.

मंजूर ने कहा, ष्करीब तीन बजे दोपहर को पुलिस का फोन आया कि आसिफ भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती है. हम वहां पहुंचे तो पता चला कि उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है. लेकिन हम आसिफ को जिंदा नहीं देख पाए.

गो-तस्करी के आरोप

भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं कोई नई नहीं हैं. पिछले एक दशक में गोकशी या गो–तस्करी के शक में हिंसा के कई मामले सामने आए हैं.

मध्यप्रदेश में ही 5 जून 2025 को रायसेन जिले में भीड़ ने दो मुस्लिम युवकों की गो–तस्करी के आरोप में पिटाई की थी. इस हमले में भोपाल निवासी 25 वर्षीय जुनैद की मौत हो गई थी, जबकि अरहम नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था.

राजस्थान विधानसभा के मार्च 2025 के सत्र में अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता भदेल ने राज्य में गो–तस्करी के मामलों की संख्या को लेकर सवाल पूछा था. इसके जवाब में गृह विभाग ने जानकारी दी कि पिछले तीन सालों में प्रदेश में कुल 880 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

इन मामलों में सबसे ज़्यादा शिकायत. ें अलवर और डीग जिले से आई हैं, जो मिलकर कुल मामलों का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा हैं. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022 में 312 केस, 2023 में 303 केस और 2024 में 265 केस दर्ज हुए. इनमें से 689 मामलों में चालान पेश किया गया, 108 में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई, जबकि 133 केस अब भी लंबित हैं.

गो–तस्करी का आरोप लगाकर भीड़ की तरफ से हिंसा पर हमने सागर सोनी से बात की. वो मध्य प्रदेश स्थित क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट के सदस्य हैं.

उनका कहना है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. अक्सर पीड़ित पर ही गोवंश वध प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है, जबकि हमलावरों पर हत्या जैसी गंभीर धाराएं नहीं लगाई जातीं.

उन्होंने कहा, कई मामलों में पीड़ित बचे भी तो उन्हें दोषी मानते हुए कानून लागू होता है. हाल ही में रायसेन में एक मुस्लिम युवक की मौत के बाद भी ऐसा ही हुआ. मध्य प्रदेश में तो कई बार पीड़ितों पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की गई है. courtesy www.bbc.com

वर्ल्ड वॉर थ्री और भारत!

विकास पारिक
विदेश प्रतिनिधि (लंदन)

आज की वैश्विक व्यवस्था एक ऐसे शतरंज की तरह लगती है जहाँ हर बड़ा देश खतरनाक चालें चल रहा है, लेकिन किसी के पास भी आखिरी रणनीति नहीं है। जो युद्ध कभी क्षेत्रीय लगते थे यूक्रेन, गाजा, दक्षिण चीन सागर — अब उनमें वैश्विक असर झलकने लगा है। पश्चिमी देश थके हुए हैं, चीन आक्रामक है, रूस अडिग है और अमेरिका की नैतिक साख गिर रही है। अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि इक्कीसवीं सदी एक और विश्व युद्ध की ओर फिसल सकती है।

भारत के लिए यह दूर की राजनीति नहीं है। अगर वर्ल्ड वॉर थ्री छिड़ता है, तो वह व्यापारिक मार्गों, गठबंधनों और ताकत के समीकरणों को ऐसे बदलेगा जो या तो भारत की उभरती ताकत को रोक देंगे या उसे एक नए वैश्विक केंद्र में बदल देंगे। राष्ट्रवादी दृष्टि से देखा जाए तो यह पीछे हटने का समय नहीं, बल्कि तैयारी का समय है कृ सैन्य शक्ति, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का समय।

वैश्विक आग के मोर्चे

आज की दुनिया के पाँच सबसे खतरनाक मोर्चे कृ यूक्रेन, ताइवान, मध्य पूर्व, कोरियाई प्रायद्वीप और भारत–चीन सीमा मिलकर एक बड़े संघर्ष का जाल बुन रहे हैं।

यूरोप में रूसदृयूक्रेन युद्ध एक लंबा खिंचा हुआ प्रॉक्सी वॉर बन चुका है। रूस और नाटो के बीच यह टकराव किसी एक की जीत नहीं, बल्कि दोनों की थकान का प्रतीक है। नाटो का लगातार विस्तार रूस को और उकसा रहा है, जबकि परमाणु चेतावनियाँ अब सामान्य शब्दावली बन गई हैं। यह युद्ध किसी समाधान की ओर नहीं बढ़ रहा कृ बल्कि अगले विस्फोट के लिए जमीन तैयार कर रहा है। एशिया में चीन की ताइवान को मिलाने की महत्वाकांक्षा वर्ल्ड वॉर थ्री का सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकती है। अगर बीजिंग हमला करता है, तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। परिणामस्वरूप पूरा इंडो–पैसिफिक क्षेत्र युद्ध का मैदान बन जाएगा, जिससे वैश्विक व्यापार ठप पड़ जाएगा। भारत के लिए यह स्थिति सबसे खतरनाक होगी कृ एक विजयी चीन एशिया का एकछत्र शासक बन जाएगा, जो भारत के उदय को दबा देगा।

मध्य पूर्व एक और ज्वालामुखी है। इज. राइल और ईरान के बीच चल रहा परोक्ष युद्ध हर पल भड़क सकता है। अगर होरमुज की खाड़ी बंद होती है, तो विश्व के 20 प्रतिशत तेल की आपूर्ति रुक जाएगी। अमेरिका या ईरान के सीधे युद्ध में आने से पूरा इलाका जल सकता है। भारत के लिए, जो अपने तेल का अधिकांश आयात करता है, इसका मतलब होगा महँगाई, सप्लाई संकट और घरेलू आर्थिक दबाव।

उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर दुनिया को चौंका रहा है, और हिमालय में भारत–चीन की सीमा पर तनाव अभी भी सुलग रहा है। गलवान की झड़पों ने दिखाया कि "शांत सीमा" का भ्रम कभी भी टूट सकता है। अगर दुनिया यूरोप या ताइवान पर केंद्रित रहती है, तो चीन दोबारा भारत को परख सकता है।

ये सारे संकट दरअसल एक ही कहानी के हिस्से हैं एक ढहती हुई विश्व व्यवस्था की। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी गठबंधनों की उपयोगिता घट रही है। नई विभा. जन रेखाएँ बन रही हैंरू एक ओर नाटो और उसके इंडो–पैसिफिक सहयोगी, दूसरी ओर चीन–ईरान का गठजोड़, और इनके बीच भारत संतुलित, आत्मविश्वासी, लेकिन किसी का गुलाम नहीं।

भारत का राष्ट्रवादी सिद्धांतरू शक्ति, आत्मनिर्भरता और सभ्यता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने एक स्पष्ट राष्ट्रवा. दी रंग लिया है। यह चार सिद्धांतों पर आधारित है कृ रणनीतिक स्वायत्तता, अडिग सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव और यह विश्वास कि भारत का समय आ चुका है। रूसदृयूक्रेन युद्ध में भारत का "तटस्थ" रुख दरअसल एक घोषणा थी कृ हम किसी के दबाव में नहीं हैं। नई दिल्ली रूसी तेल खरीदती है क्योंकि वह सस्ता है, न कि किसी विचारधारा के कारण। चीन के खिलाफ पश्चिम के साथ सहयोग करती है, लेकिन पश्चिम की कठपुतली नहीं बनती। यही है रणनीतिक स्वायत्तता।

राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारत को केवल एक आधुनिक राष्ट्र नहीं बल्कि एक प्राचीन सभ्यता के रूप में देखता है। अब नेहरूवादी आदर्शवाद की जगह कौ. टिल्यीय यथार्थवाद ने ले ली है। मोदी का वाक्य "यह युद्ध का युग नहीं है" दुनिया के लिए संदेश था कृ भारत किसी के युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, पर किसी से डरेगा भी नहीं।

इस सोच की जड़ें गहरी हैं कृ धर्म, संतुलन और धर्मपरायण शक्ति के भारतीय सिद्धांत में। पश्चिम जहाँ वर्चस्व चाहता है और चीन जहाँ नियंत्रण, भारत वहाँ आदर्श बनकर नेतृत्व करना चाहता है कृ एक सशक्त लेकिन शांत सभ्यता के रूप में।

सैन्य तैयारीरू निर्भरता से प्रतिरोध तक

बीते शताब्दी ने भारत को सिखाया कि बिना शक्ति के शांति टिकती नहीं। आज का भारत इस सत्य को अपनाकर अपनी सेना को नयी ऊँचाइयों तक ले जा रहा है। भारत अब लगभग 80 अरब डॉलर सालाना रक्षा खर्च करता है कृ दुनिया में तीसरे नंबर पर। उसके पास थल, जल और वायु तीनों में परमाणु प्रतिरोध की क्षमता है। अग्निदृ5 मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस तक, भारत की मारक क्षमता अब किसी भी दुश्मन को सोचने पर मजबूर करती है।

आत्मनिर्भर भारत ने रक्षा उत्पादन का चेहरा बदल दिया है। जो देश कभी हथियारों के आयात पर निर्भर था, अब सालाना 23,000 करोड़ रुपये से अधिक के हथियार निर्यात कर रहा है। लक्ष्य है कृ आत्मनिर्भरता और रणनीतिक प्रभाव।

भारत के गठबंधन लचीले हैं। अमेरिका के साथ क्वाड में सहयोग, रूस से संयुक्त परियोजनाएँ, इजराइल से तकनीक, फ्रांस और जापान से समुद्री साझेदारी कृ सब कुछ राष्ट्रहित पर आधारित है, न कि गुट. बंदी पर। अब भारत दो मोर्चों वाले युद्ध की तैयारी कर रहा है कृ चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ। हिमालय में नई पर्वतीय कोर, अरुणाचल और लद्दाख में एयरबेस, और हिंद महासागर में नौसैनिक निगरानी कृ सब इसी तैयारी का हिस्सा हैं। ड्रोन, साइबर युद्ध और उपग्रह आधारित खुफिया तंत्र अब भारतीय रक्षा रणनीति के केंद्र में हैं। अब भारत शांति की भीख नहीं माँगता, बल्कि उसकी कीमत तय करता है।

आर्थिक मोर्चा

भविष्य के युद्ध बंदूकों से ज़्यादा तेल, चिप्स और सप्लाई चेन से लड़े जाएँगे और यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती भी है, ताकत भी।

भारत अपने 85 प्रतिशत तेल का आयात करता है। किसी लंबे युद्ध या खाड़ी संकट से कीमतें आसमान छू सकती हैं। लेकिन भारत ने रणनीतिक तेल भंडार, विविध आपूर्तिकर्ता और नवीकरणीय ऊर्जा पर बड़ा निवेश करके तैयारी शुरू कर दी है।

अगर ताइवान पर युद्ध हुआ, तो सेमी. कंडक्टर सप्लाई रुक जाएगी मोबाइल, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स सब ठप पड़ सकते हैं। इसके लिए भारत ने घरेलू चिप निर्माण संयंत्र लगाने की नीति शुरू की है और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं (पीएलआई) के जरिए "चाइना 1" रणनीति अपनाई है।

भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि व्यापारिक अवसरों का शिल्पी बन रहा है। रूस से तेल लेकर उसे यूरोप को बेचना कृ यही है राष्ट्रवादी अर्थनीति का उदाहरण, जहाँ स्वहित ही सर्वोच्च नीति है। संभावित प्रतिबंधों के दौर में भारत ने रुपया व्यापार, यूपीआई इंटरनेशनल, और ब्रिक्स भुगतान प्रणाली जैसी पहलें शुरू की हैं कृ ताकि पश्चिमी दबाव का असर कम हो। राष्ट्रवादी दृष्टि में आत्मनिर्भरता का अर्थ अलगाव नहीं, बल्कि सुरक्षा है।

राजनीतिक और कूटनीतिक संतुलन

अगर वर्ल्ड वॉर थ्री हुआ, तो कूटनीति ही सबसे बड़ा हथियार बनेगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह सब से बात कर सकता है कृ वॉशिंगटन और मॉस्को से, तेल अवीव और तेहरान से, बीजिंग और ब्रसेल्स से। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की "तटस्थता" ने उसे एक पुल बना दिया कृ पश्चिम और बाकी दुनिया के बीच। आज भारत ग्लोबल साउथ का नेता है, उन देशों की आवाज जो पश्चिमी पाखंड और चीनी दबाव दोनों से थक चुके हैं। घरेलू राजनीति में, कोई भी वैश्विक संकट राष्ट्रवाद को और मजबूत करेगा। संकट के समय जनता मजबूत नेतृत्व को पसंद करती है, और मोदी सरकार यह अच्छी तरह जानती है। देशभक्ति, आत्मविश्वास और "भारत की नियति" का संदेश और तेज होगा। पर सरकार को यह भी देखना होगा कि राष्ट्रवाद अंधभक्ति या साम्प्रदायिकता में न बदले। एकता और संयम ही आंतरिक शक्ति का मूल है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुधार की माँग और तेज करेगा। मौजूदा संस्थाएँ अगर शांति कायम नहीं रख पा रहीं, तो भारत का दावा और मजबूत होगा कि अब उसे स्थायी सदस्यता दी जाए।

सभ्यतागत मोर्चा

रणनीति और अर्थशास्त्र से ऊपर है पह. चान कृ सभ्यता की पहचान। राष्ट्रवादी दृष्टि से यह सदी विचारधाराओं का नहीं बल्कि सभ्यताओं का संघर्ष है भौतिक पश्चिम, सत्तावादी पूर्व और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भारत। भारत की सॉफ्ट पावर योग, आयुर्वेद, सिनेमा, प्रवासी सम. ुदाय कृ अब सिर्फ सांस्कृतिक प्रतीक नहीं, बल्कि कूटनीतिक औजार हैं। "वसुधैव कुटुम्बकम" जैसी अवधारणाएँ सिर्फ नारा नहीं, बल्कि यह घोषणा हैं कि भारत की सभ्यता बाकी दोनों मॉडलों से अलग है। अगर विश्व युद्ध आता है, तो भारत उसे "लोकतंत्र बनाम तानाशाही" की पश्चिमी भाषा में नहीं देखेगा, बल्कि "मूल्यों के संकट" के रूप में देखेगा। भारत का संदेश होगा कृ धर्म पर आधारित संतुलन, वर्चस्व नहीं। यह कोई आदर्शवाद नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक भू–राजनीति है कृ जहाँ ताकत का स्रोत केवल हथियार नहीं, बल्कि विचार हैं।

भारत का निर्णायक दशक

दुनिया तनाव के किनारे खड़ी है, लेकिन भारत एक मोड़ पर है। आने वाला दशक तय करेगा कि वह इस अराजकता में उलझेगा या विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ेगा। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण कहता है कृ भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो तैयार होते हैं। भारत की तैयारी साफ दिखती है कृ रक्षा, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सब में। भारत अब किसी गुट का मोहरा नहीं, बल्कि अपना खिलाड़ी है।

अगर वर्ल्ड वॉर थ्री आता है, तो भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कृ बचना, स्थिर रहना और दिशा देना। और अगर युद्ध नहीं भी आता, तो भी भारत को इस उथल–पुथल से और मजबूत होकर निकलना होगा। जैसा कि कौटिल्य ने कहा था कृ "राजा की शक्ति इस बात में नहीं कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि वह कितना सह सकता है।"

इंदौर के कपड़ा बाजार से मुसलमानों को क्यों निकाला जा रहा है?

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के कपड़ा बाजार में मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को काम करने से मना कर दिया गया है.

यह कोई प्रशासनिक या सरकारी आदेश नहीं है बल्कि इंदौर–4 विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ का श्फरमानश है.

इस मामले पर बीबीसी ने एकलव्य गौड़ से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया.

शीतलामाता कपड़ा बाजार के अध्यक्ष हेमा पंजवानी ने बताया कि 25 अगस्त को बंद कमरे की एक बैठक में एकलव्य सिंह गौड़ ने व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बात की थी. इसी बैठक में शीतलामाता कपड़ा बाजार के व्यापारियों के प्रतिनिधियों के लिए यह फरमान जारी किया.

इसके बाद एकलव्य सिंह गौड़ ने स्थानीय मीडिया को कई बार दिए अपने बयान में कहा, श्मेरे पास कई बार लव जिहाद की शिकायतें आ चुकी हैं. यह षडयंत्र अब कोई कल्पना या मनगढ़ंत बात नहीं है. हमारे कपड़ा बाजार में ज़्यादातर महिलाएं आती हैं और मुस्लिम सेल्समैन उन्हें लव जिहाद में फंसा लेते हैं.

हालांकि एकलव्य सिंह गौड़ भले ही निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन बाजार में उनका दबदबा है.

शीतलामाता कपड़ा बाजार के अध्यक्ष हेमा पंजवानी ने बीबीसी से कहा, हमारे एकलव्य भैया का आदेश था कि बाजार से मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को बाहर निकला जाए. उनके पास कई बार लोग लव जिहाद के मुद्दे को लेकर गए थे.

बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एजाज अंसारी ने कहा कि वो फिलहाल टूर पर हैं और लौटने के बाद इस मामले को डिटेल में समझेंगे और फिर उचित कदम उठाएंगे.

इंदौर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बीबीसी से कहा कि अब तक उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है.

वहीं, विधायक मालिनी गौड़, मेयर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर बीजेपी अध्यक्ष सुमित शर्मा और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. इस बीच जिहादी मानसिकता से छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद के पा. `स्टर इंदौर के बाजार में कुछ और हकी. कत बयां कर रहे हैं.

लगभग 200 मुस्लिम कर्मचारियों की रोजी रोटी का संकट

बीबीसी की टीम जब इस मामले के तह तक जाने के लिए 25 सितंबर को इंदौर पहुंची तो कई मुस्लिम सेल्समैन नौकरी से निकाले जा चुके थे और कई मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकानें खाली कर चुके थे या करने वाले थे.

बाजार में नौकरी से हटाए गए एक मुसलमान ने कहा, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. हमारी दिक्कतें ये हैं कि बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, घर का राशन खरीदना है, लोन चुकाना है. और अगर हमें काम ही नहीं करने दिया जाएगा तो हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे?

दरवाजे की ओट पर खड़ी पत्नी की ओर देखते हुए सलमान कुछ देर रुक जाते हैं. अपनी हिम्मत और आंसू दोनों को बांधते हुए सलमान कहते हैं, कम से कम सुकून से कमाने और खाने तो दिया जाए. ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है

सलमान जैसे ही कई सेल्समैन

बाजार में लंबे समय से काम कर रहे एक मुसलमान युवक ने कहा, मैंने लगभग 16 साल इस बाजार को दिए हैं. मैं बच्चे से जवान यहीं हुआ हूं और अब दो बच्चों का बाप हूं. अब 15–20 दिन से बेरोजगार हूं. कहां जाऊं? क्या करूं–समझ नहीं आताष

भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक देशदीप सक्सेना कहते हैं, इस पूरे प्रकरण से यह सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है? क्योंकि इस मामले में संवैधानिक मूल्यों का ह्रास और अधिकारों का हनन स्पष्ट है.

जीवन जीने का अधिकार, नौकरी या काम करने का अधिकारदृ एक समुदाय के लोगों से उनके धर्म के आधार पर छीना जा रहा है. समता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों का ह्रास और प्रशासन से लेकर शासन और वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है.

मुस्लिम पार्टनर इसलिए हिंदू व्यापारी से भी दुकान खाली करवाई

आदिल और सुखविंदर पार्टनरशिप में दुकान चलाते हैं. एकलव्य सिंह गौड़ के फरमान के बाद आदिल और सुखविंदर को भी दुकान खाली करनी पड़ी. जब हम उनकी दुकान पर पहुंचे तो वहां काम करनेवाले छह सेल्समैन सारा सामान पैक कर रहे थे.

बीबीसी से बात करते हुए सुखविंदर कहते हैं, मैं हिन्दू हूं और मेरा पार्टनर मुस्लिम है. हम 20 साल से साथ काम कर रहे हैं. एकलव्य सिंह गौड़ ने लव जिहाद का आरोप लगाया, लेकिन हम पूछते हैं कि अब तक ऐसा एक भी मामला सामने आया है क्या?

आदिल कहते हैं, हमारे कारण हमारे पार्टनर की भी रोजी रोटी छिन गई. अब हम क्या करेंगे? सुखविंदर ने आदिल के कंधे पर हाथ रखा और हमसे पलटकर कहा, इस देश में कानून है, सरकार–प्रशासन है. एकलव्य सिंह गौड़ जी उनसे आगे चलकर अपना कानून तो नहीं चला सकते हैं न?

बाजार के चुने हुए अध्यक्ष क्या बोले?

इंदौर कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष हेमा पंजवानी कहते हैं, हिंद रक्षा संगठन के हमारे भैया एकलव्य सिंह गौड़ का आदेश था हम उसका पालन कर रहे हैं. उन्होंने हर दुकानदार को बुलाकर समझाया कि बाजार में जो चल रहा है, उसको तुरंत बंद किया जाए बहुत सारे मुस्लिम लोग अब यहां से जा चुके हैं.

हमारे यह पूछने पर कि अध्यक्ष के नाते आप बताएं कि वो कौन सा कारण है जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाजार से निकाला जा रहा है, पंजवानी कहते हैं, यहां मुस्लिम सेल्समैन हिन्दू लड़कियों और महिलाओं को फंसा. कर लव जिहाद करते हैं

जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी मु. स्लिम कर्मचारी या दुकानदार के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत आई है, तो उनका जवाब था, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है.

प्रशासन और भाजपा नेताओं की चुप्पी क्या इशारा करती है?

इंदौर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया कहते हैं, अब तक ऐसा कोई मामला हमारे पास नहीं आया है.

अगर कोई शिकायत आएगी, तो हम उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे.

हालांकि 15 सितंबर को मुस्लिम सेल्सम. ेन और व्यापारियों ने मिलकर इंदौर के संभागायुक्त के नाम शिकायती ज्ञापन सौंपा था. इसके बावजूद पुलिस का यह बयान कि उनके पास कोई शिकायत लेकर नहीं आया, कई सवाल खड़े करता है.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है और मुसलमानों को काम से रोकना कानूनन अपराध है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे लेकर टिप्पणी से बचते हुए कहा, पार्टी सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य पर काम कर रही है।

इंदौर में मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों के बहिष्कार के फरमान पर अग्रवाल कहते हैं, हम यह तय करेंगे कि किस मामले पर पार्टी अपना बयान या मत रखती है.

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, कोई भी हिन्दूवादी एजेंडे से इतर नहीं दिखना चाहता है. यह कुछ ऐसा ही है कि अगर कोई सांप–सांप चिल्ला दे तो सब लोग वही चिल्लाएंगे, भले ही उन्हें ये मालूम हो कि सांप नहीं रस्सी पड़ी है. क्योंकि नेताओं में कट्टर राजनीति से अलग हटकर दिखने की हिम्मत नहीं बची है.

जब हर तरफ से मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों के लिए जीवन यापन का संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में कुछ हिन्दू व्यापारी इस फरमान का विरोध भी कर रहे हैं.

विरोध की आवाजें

सुरेंद्र जैन दशकों से मुसलमान कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं.

वो कहते हैं, हम लोग सारा काम मुसलमानों के साथ करते आ रहे हैं. मेरे यहां दो मुसलमान काम करते हैं. साड़ी के फॉल–पिको से लेकर एम्ब्रॉयडरी तक का काम मुस्लिम भाई ही करते हैं. मेरी दुकान में तो ज़्यादातर मेरी पत्नी ही बैठती हैं. मेरे यहां के दोनों सेल्समैन से हमें कोई शिकायत नहीं है. हमारे यहां जो महिलाएं खरीददारी करने आती हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है, तो मैं कैसे किसी को उसके धर्म के आधार पर निकाल दूं? उनकी पत्नी राजकुमारी जैन कहती हैं, 20 साल से ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं लेकिन कोई शिकायत नहीं आई. हमारे लिए तो ये बच्चे जैसे हैं.

शीतलामाता मार्केट में दशकों से हिंदू और मुसलमान साथ–साथ व्यापार करते आए हैं. लेकिन अब माहौल बदल रहा है. स्थानीय नेताओं के बयानों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं की चुप्पी ने इस तनाव को और गहरा किया है.

फिलहाल, मुसलमान सेल्समैन और व्यापा. रियों के लिए रोजगार खोने का डर और सामाजिक असुरक्षा का अनुभव शहर के माहौल को बदल रहा है.

courtesy www.bbc.com

व्यंग्य **राजीव कुमार ओझा**

रफूगरी का है जमाना

बिहार की सियासी गलियों की हलचल ,पल में तोला, पल में माशा की गति दुर्गति पाते टिकट पाऊ ,टिकट गँवाऊ सियासी नमूनों की कुटिल मुस्कान ,कुर्ता फाड़ लालटेनी नमूने के रुदन की इंद्रधनुषी छटा बिहार के सियासी क्षितिज पर छाई है। जब से चुनावी घड़ी आई है बिहार की महिलाओं की बन आई है। भगवा पल्टन और लालटेनी पल्टन ने ठान लिया है की बिहारी महिलाओं पर इतनी कृपा बरसाओ की वो हरियाई , केसरियाई चुनर ओढ़ अपने अपने कृपालु चुनर दाता के लिए जीतो जीतो रे लला गाती ईवीएम माई के दरबार में खींची चली आएं।नया दौर है ,पुरनका वाला होता तब उनके कर्णकोटरों में मारो ठप्पा तान के वाले नारे की अगली लाइन गूंजती और वो ठप्पा तान के या पहचान के मारतीं या ना मारतीं पर मारतीं जरूर। अब नया दौर है , महाठगिनी माया से भी मायावी ईवीएम वाला। नर प्रजाति मायावी चमकती दमकती ,लुपलुपाती ,जुगनू सी जलती बुझती ,पीं पीं करती मायावी ईवीएम को देख कंफ्यूजियाती है या नहीं लेकिन रंगी पुती किसिम किसिम की नारियां कन्फ्युजिया जाती हैं ।यह नारे और नाकारे पैदा करने वाले नाकारे महारथियों के लिए डूब मरने की बात है की आज तक मारो ठप्पा तान के जैसा फड़कता नारा ईवीएम के दर तक पहुंचे नर नारियों की सुभिता के लिए पैदा नहीं कर पाए। उम्मीद पर दुनिया के कायम होने के दावे हमें उम्मीद बंधाते हैं की एक दिन ऐसा आएगा जब ईवीएम के लिए भी मारो ठप्पा तान के जैसा लोक लुभावन नारा पैदा करने वाला कोई वीर अवतार लेगा।

बहरहाल बात केसरियाई ,हरियाई चूनर से शुरू हुई और जा पहुँची नारा पैदा करने की चुनौती तक। क्यों न लगे हाँथ बात मदर आफ डेमोक्रेसी की ईवीएम मदर के चमत्कारी गुणों के सबब जायज वोटों से नाजायज नतीजों की भी की जाए। न्यू इंडिया में ईवीएम मदर की कोख से पैदा होने वाले नतीजों को लेकर कुकुरहांव बदस्तूर जारी है। नाजायज नतीजों से शुरू हुई बात मदर आफ डेमोक्रेसी के फादर (जो ज्ञान के गुप्त ईश हैं) की मक्कारी ,कलाकारी के सबब वोट चोर गद्दी छोड़ तक आ पहुँची है। सबसे बड़की अदालत तारीख तारीख खेलती रही और बिहार का चुनावी रण सज गया,तारीखों का अंतहीन खेल जारी है। गद्दी छोड़ ..ना छोड़ब ,तू चोर .तू डकैत ,तू भ्रष्ट ,तू भ्रष्ट शिरोमणि ,तू बलात्कारी ,तू समलैंगिक गैंग की महामारी की मिसाइलों ने मंहगाई ,बेरोजगारी ,पढाई ,दवाई की वाहियात चिंता से बिहारियों को मुक्त कर इस चिंता में फंसा दिया है की कोई वोटाभिलाषी आए और फौरी कृपा कपडा लत्ता ,दारु वारु के साथ तेल मसाला ,चीखना विखना के नाम पर टेंट गरम कर जाए। वोटाभिलाषी इस मुगालते में रहता है की उसकी कृपावृष्टि कबूलने वाला वोट पक्का और वोटोत्सुक नर नारी वोटाभिलाषी के गुजरते ही मन ही मन उस पर गालियों के रिटर्न गिफ्ट की कृपा वृष्टि करते है। वोटोत्सुक नर नारी किसी भी वोटाभिलाषी को वह धरती पकड़ हो या तुर्रम खां निराश नहीं करता ,उदारता से वोटाभिलाषी की गिफ्ट सर माथे चढ़ाता है और हमारा वोट पक्का की घुट्टी पीला कर विदा करते हैं। नर नारियों की चुनावी लिबास की बात हो और चुनाव लड़ासे महारथियों के गठ बंधनी –ठगबंधनी लिबास की बात ना हो तब अब तक की बात वाहियात समझ पाठक इस अकिंचन को न जाने कैसी कैसी उपाधियाँ बैठे ठाले थमा दें। गठबन्धनी –ठगबंधनी गैंग के सरगनाओं की झुमका सम्हालूं की तोहें बालमा जैसी दशा का लुत्फ खबरिया चौनलों की मुर्गा लड़ाऊ झांव झांव ,एक दूसरे की टांग खींचने ,घसीटने की कवायद में सियासी लिबास की दशा कुछ कुछ ऐसी है–

कहाँ कहाँ तू रफू करेगा
मेरे रफूगर तू ही बता दे।।
लिबास– ए – हस्ती भसक रही है
कभी इधर से कभी उधर से।।

“बौल्या काका” नवंबर के पहले सप्ताह में होगी, दिल्ली एनसीआर में रिलीज

सुनील नेगी
ब्यूरो प्रमुख, उत्तराखंड

“बौल्या काका” नामक एक रोचक और प्रभावशाली गढ़वाली फिल्म, जो देहरादून और उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में पहले ही रिलीज हो चुकी है, नवंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी और एनसी. आर में रिलीज होगी।

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शिव नारायण सिंह रावत, जो फिल्म निर्माण में पारंगत हैं और जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन मुं. बई, बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में बिताया है, द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत के सं. रक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है।

फिल्मों को समाज का दर्पण मानते हुए, रावत का दृढ़ मत है कि फिल्में हमारे समाज को बेहतर बनाने और उसके अच्छे–बुरे पहलुओं को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ताकि दर्शक समाज को बेहतर बनाने और उसे बेहतर नागरिक बनने के योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

गढ़वाली बोली में उनकी फिल्म बोल्या काका ने देहरादून और अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया है, जो नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली और एनसीआर में रिलीज हो रही है, यह एक उत्कृष्ट गढ़वाली फिल्म है जो उत्तराखंड, विशेष रूप से युवाओं के ज्व. लंत मुद्दों और उनके समाधान को उठाती है। यह फिल्म विशुद्ध रूप से उत्तराखंड के सामाजिक–सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करने के सर्वोत्तम प्रयासों का परिणाम है, जिसमें युवाओं के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया है और मौजूदा बुराइयों और शिकायतों का समाधान खोजा गया है।

शिव नारायण सिंह रावत द्वारा गढ़वाली बोली में निर्मित, एक कुशल फिल्म निर्माता, ष्बौल्या काकाष जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, तीन मुख्य पात्र हैं। मुख्य पात्र, बौल्या काका सहित ये तीनों मुख्य पात्र एक बस में बैठे हैं। बस उत्तराखंड की पहाड़ियों में मनमोहक, शांत स्थानों

से होकर गुजर रही है। बौल्या काका एक पात्र से उसकी कहानी के बारे में पूछते हैं और फिर उस पात्र का फ्लैशबैक शुरू करते हैं। इसी प्रकार, बस में बैठे काका अन्य पात्रों की कहानी के बारे में भी पूछताछ करते हैं, जिससे अन्य पात्रों का फ्लैशबैक शुरू होता है। इसके बाद फिल्म निर्माता बारी–बारी से सभी पात्रों के फ्लैशबैक दिखाना शुरू करता है, जिससे विभिन्न पात्रों की अलग–अलग शिकायतें, समस्याएं आदि और उनके समाधान आदि दर्शाए जाते हैं।

सभी पात्र प्रतीकात्मक रूप से उत्तराखंड की समस्याओं से निपटते हैं, जिससे विभिन्न समस्याओं, शिकायतों और उनके समाधानों को दर्शाया जाता है। बस में सवार पात्र महिलाएँ और पुरुष हैं, जिनके फ्लैशबैक फिल्म को रोचक और देखने लायक बनाते हैं। बॉलीवुड के प्रसिद्ध डॉक्टर, जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है, हेमंत पांडे फिल्म के मुख्य किरदार बौल्या काका (एक तरह से पागल दिखने वाले चाचा) की भूमिका निभा रहे हैं।

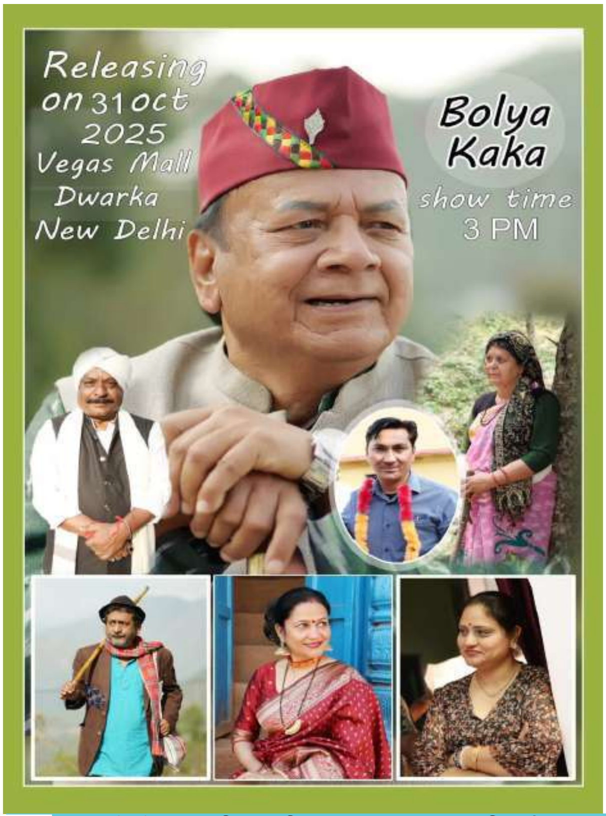

फिल्म के अन्य पात्र हैं :

यशस्वी, प्रीत घनश्याला, भरत शाह, कुँवर सिंह रौथाण, अनीता देवी, किमी गायत्री,रमेश चंद, धीरेंद्र सिंह, नितीश कुमार, महिपाल सिंह, हुकुम सिंह, रंजना फर्स्वाण,यशोदा जोशी, तन्मय सिंह, एसपी सिंह, नरेंद्र सिंह, हिम्मत सिंह, रेबुली देवी, सुनीता देवी, कमला देवी, विक्रम सिंह, बसंती देवी।

बॉयस ओवर कलाकार: भूपेश कैंतुरा।

उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, उत्तराखंड सरकार, इस फिल्म के निर्माण में फिल्म क्रू के लिए अत्यंत सहायक रही है। फिल्म के निर्माता प्रशांत कुमार और सह–निर्माता अभिषेक कुमार और प्रेमलता हैं। फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर दीपिका और श्वेता हैं। फिल्म का लेखन और निर्देशन शिव नारायण सिंह रावत ने किया है और संगीत विनोद चौहान ने दिया है। गढ़वाली फिल्म के गीतकार ध्रुपद उकी हैं, जबकि संवाद जागेश्वर जोशी ने लिखे हैं। फिल्म का कुशल संपादन रौन नेर ने किया है और इसका नृत्य निर्देशन असलम खान ने किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर–साउंड–मिक्सिंग न्यू रेज स्टूडियो ने किया है। फिल्म के लेखक और निर्देशक शिव नारायण सिंह रावत के अनुसार, पहली बार एक अलग दृष्टिकोण के साथ बनाई गई इस फिल्म की उच्च गुणवत्ता वाली छायांकन, पटकथा, संगीत, गायन और लोकेशन को देखते हुए, यह फिल्म हाउसफुल रहेगी। फिल्म का पोस्टर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने कार्यालय में जारी किया।

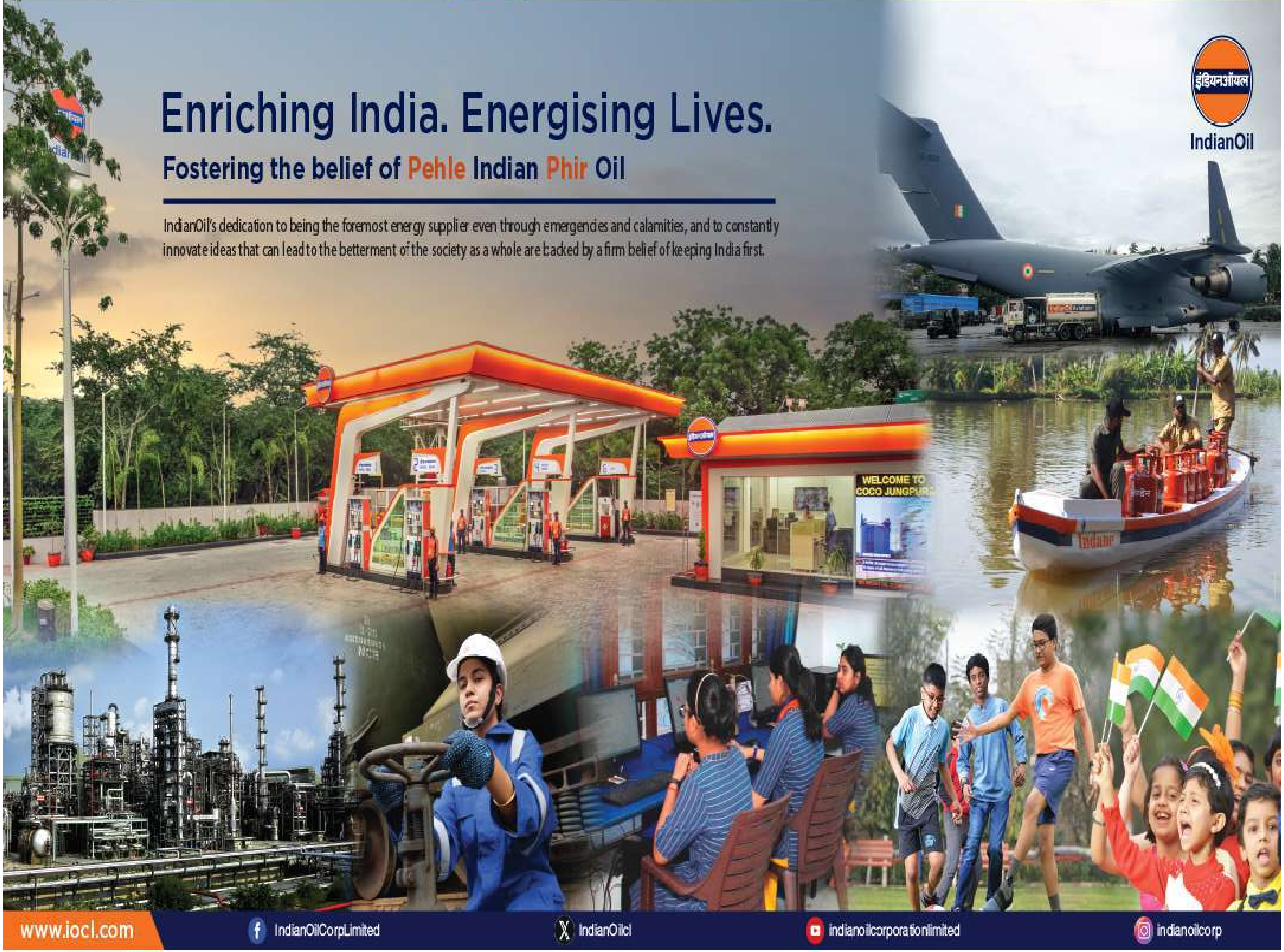
इंडियनऑयल
IndianOil
Enriching India. Energising Lives.
Fostering the belief of Pehle Indian Phir Oil
IndianOil's dedication to being the foremost energy supplier even through emergencies and calamities, and to constantly innovate ideas that can lead to the betterment of the society as a whole are backed by a firm belief of keeping India first.
WELCOME TO
COCO JUNGPURA
www.iocl.com
IndianOilCorpLimited
IndianOilcl
indianoilcorporationlimited
indianoilcorp

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
A MAHARATNA COMPANY

OF DRIVING EXPONENTIAL GROWTH
& POWERING INFINITE POSSIBILITIES

Q1 FY26 FINANCIAL RESULTS

Net Profit	Disbursements	Total Loan Book
₹ 4,451 CRORE 29%	₹ 59,508 CRORE 36%	₹ 5,84,568 CRORE 10%

Follow us on: @RECLindia
E-mail: contactus@recindia.com | Website: www.recindia.nic.in